1. राजस्थान समसामयिक

हरिभाऊ किसनराव बागड़े राजस्थान के नए राज्यपाल बने

- हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजस्थान का नया राज्यपाल (45वें राज्यपाल) नियुक्त किया गया।
- श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली।
- राजथान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने श्री बागड़े को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई।
- राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट पढ़कर सुनाया।
- हरिभाऊ किसनराव बागड़े महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 से लेकर 2019 तक अध्यक्ष रह चुके हैं।
- इससे पहले वे महाराष्ट्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, होर्टीकल्चर मंत्री भी रह चुके हैं।
- बागड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से हैं।
- यह 1985 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे।
- राजस्थान के श्री गुलाब चंद कटारिया (पहले असम के राज्यपाल थे) को पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है।
- राजस्थान के भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
- नोट: एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

श्री मोहन लाल लाठर

- राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 9 जुलाई 2024 को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री मोहन लाल लाठर को नियुक्त किया।
- श्री मोहन लाल लाठर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी है यह राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) रह चुके हैं।
- इसके अलावा श्री सुरेश चंद गुप्ता, श्री महेंद्र कुमार पारख और श्री टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

राज्य सूचना आयोग

- स्थापनाः 18 अप्रैल, 2006 को। (राजपत्र में 13 अप्रैल 2006 को अधिसूचित हुआ।)
- राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है।
- संरचनाः 1 अध्यक्ष +10 सदस्य
- वार्षिक प्रतिवेदनः राज्य सरकार को।
- प्रथम अध्यक्षः एम. डी. कोरानी।

जस्टिस एस चन्द्रशेखर

- केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने 03 जुलाई 2024 को झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस चन्द्रशेखर का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट में कर दिया।
- जस्टिस चन्द्रशेखर के नियुक्त होने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 (मुख्य न्यायाधीश सहित) हो गई है। (1+32)
- राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश है-
  1. रेखा बोराणा
  2. डॉ. नुपूर भाटी
  3. शुभा मेहता

राजस्थान नागरिक विमानन नीति, 2024

- राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति, 2024 को 02 जुलाई 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
- यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमान सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है।
- इसके तहत **किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल** खोले जाएंगे।
- **कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट** बनाया जाएगा।
- इसके अलावा **जयपुर में एयरोसिटी** बनाई जाएगी, जिसमें होटल, रेस्त्रं सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- राज्य के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रारंभ की जाएगी।
- राज्य की पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत कर पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा।

अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 में संशोधन

- राजस्थान में 02 जुलाई 2024 को अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत

संयंत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

- राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने के लिए आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है।
- इससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5%पर किया जा सकेगा।
- अब 2 हेक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा।
- इससे राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

राजस्थान सहित देश में 3 नए कानून लागू

- नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 01 जुलाई 2024 से लागू हो गए।
- इसके तहत देश में पहला केस मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया।
- राजस्थान में इन कानूनों के तहत पहला मामला पाली के सादड़ी थाने में दर्ज हुआ।

3 नए कानून

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
- भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)
- इन कानूनोंको लोकसभा में 20 दिसम्बर, 2023 को तथा राज्यसभा में 21 दिसम्बर, 2023 को पारित किया गया।
- इन्हें राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसम्बर, 2023 को हस्ताक्षर कर अधिनियमित कर दिया गया।

'ए-हेल्प (A-HELP)' योजना

- यह योजना 1 जुलाई 2024 को राजस्थान में लागू की गई।
- 'A-HELP': Accredited Agent for Health and Extension of Livestock Production.
- यह योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
- उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है।
- वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है।
- इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है।
- इस योजना के माध्यम से पशु सखियों के एकजुटता से पशुपालकों से जुड़ने पर केवल पशुधन उत्पादों में वृद्धि होगी, बल्कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
- ए- हेल्प ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत पशुपालकों को घर पर ही पशु सखी के माध्यम से पशुपालन संबंधी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है।
- राजस्थान में 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्थान हेतु केंद्रीय बजट 2024-25 में किए गए प्रावधान

- **4.46 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा**
  - केंद्र सरकार ने इस पूर्ण बजट में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को आगामी पांच वर्ष तक मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा की है।
  - राजस्थान में इस योजना के तहत 4.46 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें भी अगले पांच साल तक इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा।
- **किसानों को तिलहन मिशन का लाभ**
  - दलहन-तिलहन के लिए नए मिशन एवं इनके उत्पादन, भंडारण व मार्केटिंग के विशेष प्रयास की घोषणा की गई है।
  - इससे राजस्थान के 86.66 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रदेश में हर साल 80 लाख टन दलहन, 82 लाख टन तिलहन होता है। सरसों का ही 60 लाख टन उत्पादन है।
- **मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट**
  - जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करीब 1578 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। 922 करोड़ लागत आएगी।
  - 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
  - यह दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के पास विकसित हो रहा है। इससे करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा

- केंद्रीय करों के हिस्से में राजस्थान को इस बार 75,156 करोड़ रुपए मिलेंगे।
- केंद्रीय करों में पिछली बार राज्य को 66,556 करोड़ रुपए मिले थे।
- इस बार करीब 8600 करोड़ रुपए अधिक पैसा केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय करों से मिलेगा।
- नोट: केंद्रीय करों में एकत्रित कुल करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत रही है।

वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री की घोषणाएँ

- राज्य सरकार ने राज्य विधान सभा में 29 जुलाई 2024 को बजट 2024-25 पारित किया।

घोषणाएँ

- जेडीए की तर्ज पर बीकानेर और भरतपुर यूआईटी अब विकास प्राधिकरण बनेंगे।
- राजस्थान में AIIMS की तर्ज पर 750 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बनेगा इसके लिए 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है।
- कच्ची बस्तियों में पक्के घर बनाने के लिए 'आश्रय योजना' के तहत 1 लाख रु. दिए जाएंगे।
- अजमेर में आईटी पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है।

- जयपुर में द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
- राज्य में NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर का प्रावधान किया जाएगा। इससे पहले उज्जवला योजना और बीपीएल परिवारों को ही यह सुविधाथी।
- राज्य में युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ तक रियायती दर पर कर्ज मिलेगा।
- विधायकों, पूर्व विधायकों के हर साल वेतन- भत्ते, पेंशन बिना बिल लाए स्वतः बढ़ेंगे।
- 10 हजार आबादी के गांवों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनेंगे। इसके लिए 1000 करोड प्रस्तावित है।
- राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के लिए 500 की जगह 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी।
- राज्य में 5 करोड़ का बजट से इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड बनेगा।
- पाली, बाली, खींवसर, नागौर, लोहावट में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- आसींद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाकर आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- इसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर 2024 से लागू की जाएगी।
- राज्य सरकार ने समान पात्रता परीक्षा (CET) के प्रावधानों में बदलाव किया है। इसमें 40% अंक प्राप्त करने वाले भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। एससी-एसटी वर्ग को अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की प्रमुख घोषणाएं

- एससी-एसटी एवं टीएसपी फंड्स को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए किया।
- ओबीसी और ईडब्लुएस के युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
- अनुजा निगम के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- पहली बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपए तक की व्हील चेयर देने की घोषणा।
- छात्रावासों में रहने वाले बालक- बालिकाओं का मासिक अनुदान 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया।
- मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना शुरू किया जाएगी ।
- एससी वर्ग के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना शुरू किया जाएगी।

अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु टीएसपी फंड को 1,500 करोड़ रुपये किया गया

- राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण हेतु जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है।
- इस परिषद के सुझावों के अनुरूप निर्णय लेकर आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाएगा।
- राज्य विधानसभा में 30 जुलाई 2024 को आयोजित राजस्थान अनुसूचित जन- जाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक में जनजाति समुदाय के कल्याण की भावना से अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए टीएसपी फंड को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु किए गए प्रावधान

- केंद्र और राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत** राज्य के जनजाति बहुल 4,302 गांवों का चरणबद्ध विकास किया जाएगा।
- इसके प्रथम 2 चरणों में 1,566 गांवों को चिन्हित कर इनके सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम विकास योजनाएं तैयार की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य बजट में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणा जनजाति वर्ग के बालक- बालिकाओं के लिए छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में मेस भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह एवं खेल छात्रावासों के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।
- 250 नए मां-बाड़ी केंद्र खोलने तथा मां-बाड़ी केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है।
- गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना से सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास, संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना

- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बुजुर्गों और दिव्यांगों के परिवारों को घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निःशक्त हैं।
- राज्य में 2 जुलाई 2024 से इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र 8.66 लाख से अधिक चिन्हित परिवारों को घर पर ही राशन आपूर्ति कर दी गई है।
- यह पहल राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा शुरू की गई है।
- राज्य बजट घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है।
- इस योजना में ऐसे परिवारों को घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा निःशक्त हैं।

राजस्थान विधानसभा में भूजल संरक्षण प्राधिकरण बिल पेश

- राजस्थान में भूजल के दोहन से लेकर उसके संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण"गठित किया जाएगा

- इसके तहत 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में विधेयक पेश किया गया
- यह प्राधिकरण भूजल संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन के साथ ही भूजल का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- इसमें भूजल का उपयोग पेयजल के अलावा उद्योग, सिंचाई और वाणिज्यिक उपयोग में किए जाने संबंधी प्रावधान रहेंगे।
- इस प्राधिकरण में सीएस, एसीएस, प्रमुख सचिव या सचिव को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
- इसमें कुल 12 सदस्य होंगे।
- इसके तहत वर्षा जल के संचयन की व्यवस्था नहीं होने पर भी प्राधिकरण नोटिस देगा।
- इसमें नियम उल्लंघन पर पहली बार में 50 हजार रुपए व दोबारा ऐसा होता है तो 1 लाख जुर्माना और 6 माह जेल अथवा दोनों का प्रावधान होगा।

राजस्थान में 2365 आदर्श आंगनबाड़ी बनेंगे

- राजस्थान में 2000 आदर्श आंगनबाड़ी के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 365 आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाए जाएंगे।
- इसके अलावा बच्चों को पोषाहार के रूप में सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

राज्य सरकार की प्रमुख घोषणाएं:

- प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायतों का गठन किया गया है।
- साथिन का मानदेय 5313 से बढ़ाकर 5844 रुपए प्रतिमाह किया गया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के राज्य में अंतर्गत 50,000 के लक्ष्य के मुकाबले 85,500 पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया।
  - प्रथम बच्चे के जन्म पर देय राशि में 1500 रुपए की वृद्धि की गयी है।
  - पात्र महिलाओं को 5000 के स्थान पर 6500 रुपए मिलेंगे।
  - दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर 10 हजार रुपए देंगे।

देश में पहली बार जयपुर में बालकनी सोलर पैनल का परीक्षण

- फ्लैट में सोलर सिस्टम से विद्युत् उत्पादन करने के लिए परीक्षण हेतु 30 जुलाई 2024 को जयपुर स्थित राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (REC) के भवन में बालकनी सोलर सिस्टम लगाया गया।
- बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया।
- यह रेडी टू यूज, प्लग एंड प्ले सोलर सिस्टम है।
- एक किलोवॉट से एक माह में 100 यूनिट बिजली पैदा हो सकेगी।
- आम उपभोक्ताओं को बालकनी सोलर सिस्टम लगाने के लिए गाइडलाइन जल्दी ही जारी होगी।
- यह बालकनी सोलर सिस्टम ग्रिड से कनेक्ट नही होगा। इसमें माइक्रो इनवर्टर होगा, जिससे घर में बिजली का सीधा ही उपयोग कर सकेंगे।

एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) जयपुर में स्थापित होगा

- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)Rajasthan University of Health Sciences) जयपुर को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) के रूप में विकसित किया जाएगा।
- SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की वैकल्पिक सुविधा के साथ ही उच्च स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी
- इस पर चरणबद्ध तरीके से 750 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
- इसमें प्रसव, डायलिसिस, कैथ लैब, ट्रोमा के साथ ही एमआरआई सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होगी।
- इसमें परंपरागत चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने वालों के लिए आयुष विंग की स्थापना की जाएगी।
- इसके प्रथम चरण में ब्रॉड स्पेशलिटी फिर सुपर स्पेशलिटी और अंतिम चरण में ट्रोपिकल मेडिसन, वायरोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, जैसे विभाग बनाने की योजना है।
- दूसरे चरण में ट्रांसफ्यूजन मेडिसन, वायरोलॉजी ट्रोमेटोलॉजी, रेयर डिजीज, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे विभाग शुरू किए जाएंगे।

जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन

- नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी **रिन्यू** द्वारा 24 जुलाई 2024 को **जैसलमेर में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र** शुरू किया गया है।
- इसमें शेष 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक प्रारंभ होगा।
- इससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। इस संयंत्र द्वारा राजस्थान डिस्कॉम को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।
- रिन्यूद्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा, जिसमें 5500 मेगावाट की नवीकरणीय परियोजनाएं और महिंद्रावर्ल्ड सिटी जयपुर में 4गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र की स्थापना शामिल हैं।

रावतभाटा में 700 मेगावाट के 2 परमाणु बिजलीघर स्थापित करने हेतु सर्वे होगा

- देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए रावतभाटा में 700 मेगावाट की दो परमाणु बिजलीघर इकाइयों हेतु सर्वे किया जाएगा।
- राजस्थान के बांसवाड़ा में चार परमाणु रिएक्टर का काम भी शुरू किया जाएगा।

- रावतभाटा के अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा परमाणु रिएक्टर वाला राज्य का दूसरा स्थान होगा।
- यहां पर चार परमाणु रिएक्टर 700 मेगावाट के जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा।
- यदि रावतभाटा में दो परमाणु बिजलीघर की इकाइयां और स्थापित हुई तो यहां पर 10 परमाणु बिजलीघर इकाइयां हो जाएगी। इसके लिए 25000 करोड़ का निवेश की संभावना है।
- अभी यहाँ पहले से ही छह परमाणु बिजलीघर की इकाइयां स्थापित हैं। अभी 1100 मेगावाट की क्षमता है।
- रावतभाटा में वर्ष 2025 तक 1400 मेगावाट उत्पादन होगा। तथा 2025 तक 2500 मेगावाट की क्षमता हो जाएगी।
- यदि सर्वे के पश्चात् 2 और इकाइयां स्थापित होती है तो रावतभाटा में न्यूक्लियर एनर्जी से 3900 मेगावाट का उत्पादन होगा इससे रावतभाटा भारत का सबसे ज्यादा परमाणु रिएक्टर वाला शहर होगा।

'संपूर्णता अभियान'

- यह अभियान नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से पूरे देश में शुरू किया गया।
- यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) में चयनित देश के 112 जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) में चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है।
- इस अभियान के माध्यम से 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- राजस्थान के 5 जिले ADP और 27 ब्लॉक ABP में शामिल है। इनमें संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
- इसके तहत सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- यह अभियान 30 सितम्बर, 2024 तक चलेगा।

'एक व्यक्ति एक पेड़' अभियान

- राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 5 जुलाई 2024 को 'एक व्यक्ति एक पेड़' अभियान की घोषणा की गई।
- इसके तहत कृषि विभाग द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे।
- इस अभियान के तहत समस्त जिलों में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाये जायेंगे।
- इस अभियान हेतु फलदार और छायादार पाधों का चयन किया गया है। इनमें आम, अमरूद, आंवला, बील, जामुन, सीताफल, इमली, चीकू, शहतूत, मौसमी, नाशपती जैसे फलदार एवं नीम, पीपल, बरगद, गूलर, शीशम, बबूल, सहजन, खेजड़ी व रोहिड़ा शामिल हैं।
- पौधारोपण के बाद इसकी 4 वर्ष तक जिम्मेदारी कृषि विभाग द्वारा की जाएगी।

'पहल' योजना शिविर

- यह सलूम्बर जिला प्रशासन द्वारा की गए पहल है।
- इसके तहत हर पात्र व्यक्ति को सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- यह शिविर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होगा।
- इसमें आमजन को आधार कार्ड, जनआधार,बिजली कनेक्शन बैंकखाता, पीएम जीवन सुरक्षाबीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कैटल शेडयोजना कृषक परिवार, म्युटेशन, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना के पात्र, श्रम योगी मानधन योजना, ई श्रम पंजीकरण, विशेष योग्यजन, रोडवेज पास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार, कन्यादान, विवाह पंजीयन और अन्य जन कल्याणकारी योजनायें शामिल है।

'ऑपरेशन सीमा'

- यह श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की पहल है।
- इसका उद्देश्य जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम और जिले को नशा मुक्त बनाना है।
- इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा बच्चों को जागरूक किया गया।

'पोषित लाडो' अभियान

- यह 15 जुलाई 2024 से बारां जिले में शुरू हुआ।
- यह बारां में विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई पहल है।
- यह अभियान 'सशक्त बारां- प्रगति कोशक्ति' अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चलाया गया है।
- यह अभियान 15 जुलाई से 25 अक्टूबर, 2024 तक चलेगा।
- इसके तहत प्रतिमाह छात्रवासों में अध्ययनरत बालिकाओं के रक्त की जाँच कर आईएफए, एलवेंडाजोल टेबलेट, आंवला कैंडी दी जाएगी।

इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर

- ये सेंटर अभय कमांड की तर्ज पर स्मार्ट सिटी में स्थापित किए गए है।
- नोट: राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटी अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा में विकसित किए जा रहे है।
- इसका मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ते अपराध की रोकथाम में अभय कमांड सेंटर की तर्ज पर कार्य करना है।
- इसे स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापित किया गया है।
- इन्हें स्मार्ट सिटी मुख्यालय में 36 करोड़ की लागत से सेंटर बनाया है।
- इसके तहत प्रत्येक शहर में 184 कैमरे लगाए हैं, जिनके लिए 10 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं।

राजस्थानः सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तैयार करने वाला पहला राज्य

- सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगामी 10 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- इस प्लान के तहत नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
- इसका लक्ष्य प्रदेश में वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना है।
- सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से विभिन्न देशों में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को समायोजित कर राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजना तैयार होगी।
- इसका क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा।
- प्रथम चरण वर्ष 2025 से 2027, द्वितीय चरण वर्ष 2027 से 2030 और तृतीय चरण वर्ष 2030 से 2033 के मध्य संचालित किया जाएगा।

सभी तहसीलें ऑनलाइन अधिसूचित होगी

- राजस्थान की सभी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित किया जाएगा।
- वर्तमान में राजस्थान की कुल 426 तहसीलें है।
- इससे राज्य के आमजन को राजस्व संबंधी कार्य सहज एवं सुलभ उपलब्ध हो सकेंगे।

कोटा एयरपोर्ट हेतु त्रिपक्षीय एमओयू

- 19 जुलाई 2024 को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए **एयरपोर्ट अथॉरिटी, नगरीय विकास विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य** त्रिपक्षीय एमओयू हुआ।
- इस हेतु राज्य सरकार एयरपोर्ट के लिए निःशुल्क भूमि देगी तथा निर्माण, विकास एवं संचालन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की होगी।
- कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।
- इस दौरान एएआई चेयरमैन संजीव कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एवं नागरिक उड्डयन शिखर अग्रवाल एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से हाडौती के निवासियों को हवाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य सरकार व हुडको में 1 लाख करोड़ का एमओयू

- हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) एवं राज्य सरकार के बीच 24 जुलाई 2024को एमओयू हुआ।
- इसके तहत राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
- राज्य में पानी, सिंचाई व बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) 5 साल तक राज्य सरकार को ऋण देगा।
- इसके तहत जल जीवन मिशन के लिए जल निगम को 1577 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है।

टाई राजस्थान का DOIT और आईस्टार्ट से समझौता

- टाई राजस्थान ने 6 जुलाई 2024 को महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और आईस्टार्ट राजस्थान से साझेदारी की है।
- इसके तहत टाई वुमन ग्लोबल पिच कम्पीटिशन का आयोजन किया जाएगा।
- इसमें चयनित प्रदेश की महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर एंजल इन्वेस्टर उपलब्ध कराने के साथ इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा।
- इस संयुक्त पहल से महिलाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और औद्योगिक विकास में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ेगी।

राजस्थान की 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में 01 जुलाई 2024 को राजस्थान की 8 सहकारी समितियों को 4 श्रेणियों में उत्कृष्टता और श्रेष्ठता के तहत पुरस्कार दिए गए।

4 श्रेणियों में 8 पुरस्कार

1. सर्वश्रेष्ठ पैक्स

- क्षेत्रीय उत्कृष्टताः पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीकर
- क्षेत्रीय श्रेष्ठताः 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अनूपगढ़

2. केवीएसएस

- क्षेत्रीय उत्कृष्टताः बांसवाड़ा क्रय- विक्रय सहकारी समिति, बांसवाड़ा
- क्षेत्रीय श्रेष्ठताः कोटपूतली क्रय- विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटपूतली

3. सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति

- क्षेत्रीय उत्कृष्टताः आपणी सहकारी सेवा समिति लि., माधोराजपुरा,
- क्षेत्रीय श्रेष्ठताः केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर

4. सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक

- **क्षेत्रीय उत्कृष्टताः** सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड
- **क्षेत्रीय श्रेष्ठताः** जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

नोटः राजस्थान के वर्तमान में सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक है।

राजस्थान के 2 मेजर को मरणोपरांत शौर्यचक्र

- राजस्थान के शहीद मेजर मुस्तफा बोहरा और शहीद मेजर विकास भांबू को 05 जुलाई 2024 को शौर्यचक्र प्रदान किया गया।
- राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया।
- मेजर मुस्तफा और मेजर भांबू 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल में हेलिकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए थे।

परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार

- राजस्थान में 12 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार एवं प्रशस्ति- पत्र प्रदान किए गए।
  - बांसवाड़ा (पहला स्थान)
  - ब्यावर (दूसरा स्थान)
  - केकड़ी (तीसरा स्थान)
- इसी तरह PPIUCD निवेशन में ब्यावर को प्रथम, सलूम्बर को द्वितीय तथा चित्तौड़गढ़ को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया।
- सतत् विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार कुल प्रजनन दर (टीएफआर) का लक्ष्य 2.1 है, जबकि राज्य की कुल प्रजनन दर 2.0 है।

जयपुर पांच सफारी वाला देश का एकमात्र शहर बनेगा

- जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप 30 हैक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी तैयार की गई है।
- इसे लगभग4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है।
- वर्तमान में जयपुर में झालाना में लेपर्ड आमागढ़ में लेपर्ड, आमेर में एलिफेंट और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी की सुविधा उपलब्ध है।
- टाइगर सफारी जयपुर में पांचवीं सफारी होगी तथा5 सफारी वाला जयपुर देश का एकमात्र शहर होगा।

राजस्थान के 8 शहरों में घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाई जाएगी

- राजस्थान में खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा घरेलू गैस पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
- इसके तहत 19 जुलाई को खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा सीएनजी सप्लाई करने वाली 13 सीजीडी संस्थाओं के साथ बैठक हुई।
- इसमें वित्तीय वर्ष में जयपुर-कोटा सहित 8 शहरों में 2,000 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत1 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसमें जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर और पाली में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
- इसके अलावा रीको के औद्योगिक क्षेत्रों और रीको के नए बनने वाले पार्कों में सीएनजी, पीएनजी व एलएनजी के लिए प्राथमिकता से भूमि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

नीना सिंह

- राजस्थान की पहली महिला IPS अधिकारी रही है
- नीना सिंह 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुई।
- यह 1989 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रही है
- यह नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक रह चुकी हैं।
- नीना सिंह सिरोही एसपी, अजमेर रेंज आईजी सहित कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं।

बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार

- राजस्थान में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य सरकार द्वारा बिशन सिंह शेखावत पुरस्कार दिया जाएगा।

एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक

- एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक **जोधपुर मंडल के नावां (डीडवाना-कुचामन) में** बन रहा है।
- इस पर 220 किमी प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन का भी परीक्षण किया जा सकता है।
- यह ट्रैक कुल 62 किमी लंबाई और 810 करोड़ रु. की लागत से बन रहा है तथा यह दो चरणों में तैयार होगा।
- पहले चरण में सांभर से लगे गुढ़ा स्टेशन से मीठड़ी स्टेशन तक 25 में से 9 किमी ट्रैक तैयार हो चुका है। दूसरे चरण में शेष 37 किमी लंबे घुमावदार व अंधे मोड़ वाला टेस्टिंग ट्रैक बनेगा।
- यह ट्रैक दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस ट्रैक पर रोलिंग स्टॉक और इसके घटकों, रेलवे पुल तथा भू-तकनीकी से संबंधित नई तकनीकों का भी परीक्षण होगा।

IIT जोधपुरः हिंदी में लॉन्च B.Tech लॉन्च करने वाला देश का पहला IIT

- IIT जोधपुर देश में पहला आईआईटी होगा, जहां पर हिंदी में कोर्स शुरू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के तहत इसे लॉन्च किया है।
- IIT जोधपुर में अब दो सेक्शन में होगी पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा में बीटेक किया जा सकेगा।
- हिंदी में कोर्स की लॉन्चिंग की जा चुकी है। जेईई एडवांस्ड की काउंसलिंग के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा।

श्रीगंगानगर आयुष्मान कार्ड वितरित करने में पहले स्थान पर

- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाने में श्रीगंगानगर राज्य में पहले स्थान पर है।
- श्रीगंगानगर में चिकित्सा विभाग द्वारा 1-90 लाख से अधिक पात्र परिवारों की ई- केवाईसी करने और आयुष्मान कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- श्रीगंगानगर में करीब 73% लोगों तक कार्ड पहुंचा दिया गया है, जो राज्य में सर्वाधिक है।

पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- पारंपरिक जल संरक्षण तकनीक पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2024 तक जयपुर में किया गया।
- यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया।
- इसमेंप्राथमिक शिक्षा में जल संरक्षण का अध्याय शामिल करने पर सहमति बनी।
- इसके तहत भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों जैसे बावड़ी, कुआं, जोहड़ और नाड़ी आदि का जीर्णोधार किया जाएगा।
- जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों अपनाने हेतु सरकार और प्रशासन के साथ-साथ जन सहयोग पर बल दिया गया।

इंटरनेशनल शुगर एक्सपो

- इसका आयोजन 29-30 जुलाई 2024 को सीतापुरा स्थित जेईसीसी, जयपुर में किया गया।
- इसका आयोजन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (STAI) द्वारा किया गया
- इस कार्यक्रम में शुगर इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, शुगर मिल ओनर्स, कम्पनियों के सीईओ, टेक्नोलॉजी डवलपर्स ने भाग लिया।

केंद्रीय संस्कृत विवि में संस्कृत की पढ़ाई के साथ सिविल सर्विसेज स्टडीज कोर्स भी शामिल होगा

- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर देश का पहला विवि है, जहां संस्कृत की पढ़ाई के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कराई जाएगी।
- अभी तक सिर्फ दो कैंपस जयपुर एवं लऽनऊ में बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विस स्टडीज (BA-SCS) कोर्स तैयार किया है।
- केंद्रीय संस्कृत विवि में बीए ऑनर्स इन संस्कृत एंड सिविल सर्विस स्टडीज (BA-SCS) प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें 55 सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन टेस्ट के जरिए दिया जाएगा।
- सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रओं की प्रवेश परीक्षा के अंक के आधार पर फीस में 50% तक की छूट भी मिलेगी।

जस- 2024

- इसका आयोजन 5-7 जुलाई 2024 को जयपुर में किया गया।
- इसे ज्वैलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया गया।
- जयपुर विश्व पटल पर रत्न और आभूषणों के लिए विख्यात है ।
- नोटः राज्य सरकार द्वारा 'एक जिला - एक उत्पाद' योजना के तहत जयपुर में रत्न एवं आभूषणों को चिन्हित किया गया है।
- इसके तहत राज्य सरकार इस क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करेगी।
- जेम्स ज्वैलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, साथ ही रोजगार सृजन का भी मुख्य साधन हैं।
- नोटः वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान के कुल निर्यात में रत्न आभूषणों की हिस्सेदारी 11,183 करोड़ रुपये की रही है।

भारत सोलर कंपोर्नेट एक्सपो

- राजस्थान में पहली बार 6 से 8 जुलाई 2024 तक जयपुर में भारत सोलर कंपोर्नेट एक्सपो आयोजित किया गया।
- इसका आयोजन राजस्थान सोलर एसोसिएशन (RSA) द्वारा किया गया।
- पीएम सूर्योदय योजना और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना के बाद सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है।
- इससे प्रदेश में अगले 5 साल में सोलर MSME का कारोबार 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
- यह एक्सपो उपभोक्ता और सोलर उद्योग से जुड़े लोगों को मंच पर लाने और कंपोर्नेट की जानकारी देने के मकसद से एक्सपो आयोजित किया गया।
- राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में तो शीर्ष राज्य है, लेकिन कंपोर्नेट उत्पादन में अन्य राज्यों से पीछे हैं।

राजस्थान की पहली डेंटल वैन

- RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज को राजस्थान की पहली आधुनिक मोबाइल डेंटल वैन मिली है।
- यह राजस्थान का पहला चल (**Movable**) दन्त चिकित्सालय है।
- इसमें दांतों के मरीजों का प्राथमिक उपचार के साथ- साथ दांत निकालना, सफाई और फिलिंग की सुविधा मोबाइल डेंटल वैन में ही मिल सकेगी।
- यह मोबाइल डेंटल वैन वातानुकूलित सुविधाओं से युक्त है। इसमें डेंटल चेयर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासोनिक स्केलर, एयर रोटर, कंप्रेसर आदि की व्यवस्था है।
- इसमें निःशुल्क दवा योजना के तहत अस्पताल में मिलने वाली दवाएं वैन में निःशुल्क मिल सकेगी।

'ई- साक्ष्य' एप

- यह एप राजस्थान में 5 जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया।
- यह देश में 1 जुलाई 2024 से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को एप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए है।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के द्वारा तैयार किया है।
- नए क्रिमिनल लॉज के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में किसी भी अपराध से संबंधित एवीडेंस को डिजिटल रूप में संकलित एवं सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- इस एप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से इस एप को अनुसंधान अधिकारी (IO) संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे तथा सभी प्रकार के सर्च एवं सीजर की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

- इस एप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे 'क्लाउड' पर डाल दिया जाता है, जिससे डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

राजस्थान में खनन में नीलामी के सन्दर्भ में पहले स्थान पर

- वर्ष 2015 से 2023 तक खनन क्षेत्र में कुल नीलामियों के सन्दर्भ में राजस्थान में चौथे स्थान पर रहा थाजबकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था।
- वर्ष2024 में राजस्थान पहले स्थान पर है।
- राजस्थान में वर्ष 2024 में 34 ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया पूरी की है। इनमें सोने की खदान की नीलामी भी शामिल है। इसके अलावा 28 ब्लॉक्स चूना पत्थर के, 4 लौह अयस्क के तथा 1 सिलिसियस अर्थ का नीलाम हुआ है।
- इससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने खनिज (नीलामी) संशोधन नियम 2024 लागू किए।
- इसके बाद राजस्थान एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (ईएल) जारी करने के मामले में पहले स्थान पर आ गया है।
- नए नियम के बाद राज्य सरकार ने पहला ही एक्सप्लोरेशन लाइसेंस घाटोल (बांसवाड़ा) के भूकिया जगपुरा में प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान के लिए जारी किया था।

किक बॉक्सिंग स्पर्धा में राजस्थान ने 3 पदक जीते

- वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मापुसा गोवा में हुआ।
- इसमें राजस्थान के प्रतीक बेनीवाल ने 86 किलो वर्ग श्रेणी में रजत पदक जीता।
- अंकित श्रीवास्तव ने 75 किलो वर्ग की लो किक श्रेणी में कांस्य पदक जीता।
- उन्नत सिंह ने 81 किलो वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता।

इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग

- एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन 7 से 10 नवंबर तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में होगा।
- इस लीग का लोगो व शुभंकर लॉन्च किया गया। मस्कट का नाम 'टोटो' है।
- इस लीग में पुरुषों की आठ और चार महिला टीम खेलेंगी एक टीम में 10 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 6 नेशनल एवं 3 इंटरनेशनल खिलाड़ी की मदद से पूरी टीम बनेगी।
- इस लीग में रेड रेंजर उडीसा, दिल्ली फाइटर, रॉयल चैलेंजर राजस्थान, स्टार ऑफ चंडीगढ़, यूपी राइटर, पावर स्ट्राइकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र ड्रैगन, पंजाब लायन, गेम चेंजर बैंगलोर, हैदराबाद टाइगर, गुजरात हंटर, हरियाणा बिग बुल, पिंक सिटी ईगल व मारवाड़ वॉरियर्स टीम भाग ले रही है।

पवन कुमावत ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

- कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में पवन कुमावत ने स्वर्ण पदक जीता है।
- पवन ने इन्कालाई बेंच प्रेस के 76 किलो भार वर्ग में 245 किलो वजन उठाकर यह पदक जीता।

अभ्र भाटी

- थिम्पू (भूटान) में आयोजित हुई साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में भारत की तरफ से खेलते हुए जयपुर के खिलाड़ी अभ्र भाटी ने केडेट -63 कैटेगरी में रजत पदक जीता।

जूनियर नेशनल वुशू प्रतियोगिता राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा

- तमिलनाडु में आयोजित 23वीं जूनियर राष्ट्रीय (बालक/ बालिका) वुशू प्रतियोगिता में राजस्थान वुशू टीम ने 8 स्वर्ण, 4 रजत व 7 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते।
- राजस्थान टीम ने संशोऊ वर्ग में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में दूसरे स्थान की ट्रॉफी जीती।
- इसमें कैफ मंसूरी, अभिमन्यु पारीक, वैभव शर्मा, सक्षम खंडेलवाल, किरण पारीक, प्रियांशी गौतम, दिव्यांशी, रेणुका शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता
- शिव कुमार, हिमालय जटवा, हेमेन्द्र सिंह औरछवि कंवर ने रजत पदक और कर्मवीर, रूद्र शर्मा, रुद्राक्ष अमेरिया, पियूष महेरा, प्रिया चौहान, मनीषा भाटी, ड्यूल इवेंट (वैदेही पारीक, रिद्धि पारीक, महिमा चौधरी) ने कांस्य पदक जीता है।

2. राष्ट्रीय परिदृश्य (राजव्यवस्था एवं शासन)

नीति आयोग का पुनर्गठन

- केन्द्र सरकार ने 16 जुलाई 2024 को नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया।
- पुनर्गठित नीति आयोग में चार पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री (4 पदेन सदस्य तथा 11 विशेष आमंत्रित सदस्य) हैं।

नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) (पदेन)	
नीति आयोग के उपाध्यक्ष: सुमन बेरी	
पूर्णकालिक सदस्य	**पदेन सदस्य**
• वी के सारस्वत • प्रोफेसर रमेश चंद • डॉ वीके पॉल • आनंद विरमानी	• शिवराज सिंह चौहान (कृषि मंत्री) • राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री) • अमित शाह (गृह मंत्री) • निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री)

विशेष आमंत्रित सदस्य

- नितिन गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री)
- जगत प्रकाश नड्डा(स्वास्थ्य मंत्री)
- एचडी कुमारस्वामी (इस्पात मंत्री)
- जीतन राम मांझी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री)
- राजीव रंजन सिंह (पंचायती राज मंत्री)
- डॉ वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री)
- के. राममोहन नायडू (नागरिक उड्डयन मंत्री)
- जुएल ओरांव (जनजातीय मामलों के मंत्री)
- अन्नपूर्णा देवी (महिला और बाल विकास मंत्री)
- चिराग पासवान (खाद्य प्रसंस्करण मंत्री)
- राव इंद्रजीत सिंह (योजना मंत्री)

नीति (NITI) आयोग

- पूरा नाम: National Institution for Transforming India (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)
- गठन: 1 जनवरी, 2015 को (केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा)
- नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित 'थिंक टैंक' है, जो निदेशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है तथा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।
- यह भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है इससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जुलाई 2024 को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की।
- यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें 20 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों उपराज्यपालों ने भाग लिया। /
- इस वर्ष की बैठक का विषय 'विकसित भारत@2047' है।
- इसमें विकसित भारत पर विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई।
- इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है।

1 जुलाई से तीन नये आपराधिक कानून को लागू किया गया

- भारतीय संसद द्वारा पारित तीन नये आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 की जगह ले ली; भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले लिया; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान ले लिया।

मुख्य बिन्दु

- IPC में 511 की तुलना में BNS में 358 धाराएं हैं। इसलिए, IPC में सूचीबद्ध कई आपराधिक आरोपों की संख्या बदल गई है।
- **अपराध और भारतीय न्याय संहिता की नई धाराएं**
- **हत्या का प्रयास:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 307, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत आता है।
- **बलात्कार:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 375, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अंतर्गत आता है।
- **सामूहिक दुष्कर्म:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के अंतर्गत आता है।
- **विवाहित महिला के साथ क्रूरता:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के अंतर्गत आता है।
- **दहेज हत्या:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अंतर्गत आता है।
- **यौन उत्पीड़न:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के अंतर्गत आता है।
- **महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 354, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के

अंतर्गत आता है।

- **आपराधिक धमकी (Criminal intimidation):** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 503, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के अंतर्गत आता है।
- **मानहानि:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 499, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आता है।
- **धोखाधड़ी (चीटिंग):** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 420, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के अंतर्गत आता है।
- **आपराधिक षडयंत्र:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 120ए, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के अंतर्गत आता है।
- **राजद्रोह:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अंतर्गत आता है।
- **विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना:** पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, अब यह अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंतर्गत आता है।

राज्यसभा के नियम 267 और नियम 176

- हाल ही में, राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 (Rule 267) के लगातार उपयोग के बारे में सांसदों के बीच आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया।
- **नियम 267 और नियम 176,** राज्यसभा में प्रक्रिया के विशिष्ट नियम हैं। ये नियम कार्य संचालन को रेगुलेट करते हैं और संसद सदस्यों (एमपी) को चर्चा और बहस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की अनुमति देते हैं।
- **नियम 267,** राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का हिस्सा है, जो सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर तत्काल चर्चा करने के लिए दिन भर के सूचीबद्ध विषयों को लंबित करने की अनुमति देता है।
- यदि सभापति अनुमति देता है तो प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है।
- **नियम 176** राज्यसभा में प्रक्रिया का एक और नियम है जो अल्पकालिक चर्चाओं की अनुमति देता है। ये चर्चाएँ ढाई घंटे से अधिक नहीं चलती हैं।
- नियम 267 के विपरीत नियम 176 के लिए औपचारिक प्रस्ताव या मतदान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
- अर्थात नियम 267 को किसी विषय पर तत्काल चर्चा के लिए अन्य विषयों को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि नियम 176 औपचारिक प्रस्तावों या मतदान की आवश्यकता के बिना लघु अवधि की चर्चाओं की सुविधा प्रदान करता है।

तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार है- सुप्रीम कोर्ट

- सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को फैसला दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण यानी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार है।
- न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत प्रावधान को मौजूदा पर्सनल लॉ का हवाला देकर खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि CrPC की धारा किसी धर्म का उल्लेख नहीं करती। इसलिए इसके प्रावधान सभी धर्मों पर लागू होते हैं।
- CrPC की धारा 125 के तहत यह प्रावधान है कि "पत्नी" में वह महिला शामिल है जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या उसने तलाक प्राप्त कर लिया है और उसने दोबारा शादी नहीं की है। इसमें महिला के धर्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

केंद्रीय सूचना आयोग के पास बेंच गठित करने और नियम बनाने का अधिकार हैं-सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) के पास पीठों का गठन करने और नियम बनाने की शक्तियाँ हैं।
- न्यायालय ने कहा कि आयोग की पीठों के गठन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार मुख्य सूचना आयुक्त की हैं। (RTI अधिनियम की धारा 12(4) के तहत)
- केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 12-10-2005 को किया गया।
- आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है।
- आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं।

राज्य को खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है - सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 25 जुलाई को कहा कि खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने का राज्य विधानमंडलों का अधिकार संसद के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा सीमित नहीं है।
- अर्थात**राज्य विधानमंडल को राज्य की खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है।**
- इस फैसले में कहा गया कि राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में एंट्री 49 (भूमि और भवनों पर कर) के साथ अनुच्छेद 246 के तहत खानों और खदानों पर कर लगाने की अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।
- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य सूची में यानी सूची II में वर्णित है। संसद उस विषय के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती है।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने हेतु नियमों में संशोधन

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के नियमों में संशोधन किया है।

- इस संशोधन के बाद, केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी निर्वाचित सरकार के पास आंतरिक सुरक्षा, स्थानांतरण, अभियोजन और अटॉर्नी-जनरल सहित सरकारी वकीलों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में सीमित शक्तियाँ होंगी।
- नए नियम के अनुसार, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल से अनुमोदन के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा।
- इसने राज्य पुलिस, IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।

3. आर्थिक परिदृश्य

संपूर्णता अभियान'

- नीति आयोग ने 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने के लिए 'संपूर्णता अभियान' (Sampoornata Abhiyan) शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों में सम्पूर्णता यानी शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
- 'संपूर्णता अभियान' आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme: ADP) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme) के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
• यह कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। • उद्देश्य: देश के अपेक्षाकृत पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों के तेजी से विकास को सुनिश्चित करना है • यह देश के 112 जिलों को कवर करता है	• यह कार्यक्रम-2023 में लॉन्च किया गया • उद्देश्य: देश भर के 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता प्रदान करना है।

RBI "प्रोजेक्ट नेक्सस" में शामिल हुआ

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को आपस में जोड़कर इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट की सुविधा के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल "प्रोजेक्ट नेक्सस" में शामिल हो गया है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा** तैयार की गई है।
- उद्देश्य:4 आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ना है।
- इस आशय के एक समझौते पर BIS और संस्थापक देशों और RBI ने 30 जून, 2024 को बेसल(स्विटज़रलैंड) में हस्ताक्षर किए।
- इस प्लेटफ़ॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है।

'प्रोजेक्ट परी'

- प्रोजेक्ट परी/PARI (Public Art of India) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है।
- यह प्रोजेक्ट यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरानलॉन्च किया गया।
- इसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** ऐसी कला को सामने लाना है जो आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों साल पुरानी कलात्मक विरासत (लोक कला/लोक संस्कृति) से प्रेरणा लेती हो।
- इसके तहत पहली प्रदर्शनी 21-31 जुलाई 2024को नई दिल्ली में आयोजित हुई।
- इस गतिविधि में शामिल कुछ रचनात्मक कैनवस मे राजस्थान की फड़ पेंटिंग पिछवाई पेंटिंग, बणी-ठणी पेंटिंग भी शामिल की गई।

संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना

- इसे केंद्र सरकार द्वारा 25 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:**देश के युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- यह योजना नई कौशल शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करेगी।
- यह पहल उभरती हुई औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक उच्च लागत वाले अत्याधुनिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगी।
- यह योजना 2015 में शुरू की गई कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CCFSSD) पर आधारित है।

SEHER क्रेडिट एजुकेशन कार्यक्रम

- महिला उद्यमिता मंच (WEP) और ट्रांसयूनियन CIBIL द्वारा SEHER नामक एक क्रेडिट एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया।
- यह कार्यक्रम भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता कंटेंट और व्यावसायिक कौशल के साथ सशक्त करेगा।
- इससे उन्हें देश की अर्थव्यवस्था में आगे विकास और रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

महिला उद्यमिता मंच (WEP)

- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्लेटफॉर्म है।
- इसे 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था।
- उद्देश्य: भारत में महिला उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल बनाना है।
- यह मंच WEP के फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव (FWC) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के लिए फण्ड प्राप्ति में तेजी लाना है।

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)

- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index: PPI) शुरू करने के लिए एक मॉडल को अंतिम रूप दे रहा है।
- यह सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की जगह लेगा।
- PPI को विश्व के कई देशों द्वारा अपनाया गया है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधि के मापकों को संकलित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) के अनुरूप है।
- 1970 के दशक से कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएँ WPI की जगह PPI को अपना चुकी हैं।

PPI की मुख्य विशेषताएं	WPI से PPI में बदलाव के कारण
• PPI उत्पादकों द्वारा प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है और अप्रत्यक्ष करों को बाहर रखता है। • PPI WPI में निहित बहु गणना पूर्वाग्रह को भी हटाता है। • यह करों और परिवहन द्वारा लगाए गए उत्पादों पर अतिरिक्त लागतों को कम करने से मूल्य में उतार-चढ़ाव को अधिक सटीकता से मापता है। • PPI में भार आपूर्ति उपयोग तालिकाओं से प्राप्त किया जाता है। • PPI में सेवाएँ भी शामिल हैं जबकि WPI में केवल वस्तुएँ हैं।	• WPI में वस्तुओं की दोहरी/बहु गणना के पूर्वाग्रह को दूर करना • अपस्फीतिकारक के रूप में उपयोग के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के साथ वैचारिक रूप से सुसंगत सूचकांक संकलित करना। • चीन सहित G-20 के सभी सदस्यों ने PPI अपना लिया है।

डिजिटल भारत निधि

- हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने डिजिटल भारत निधि (Digital Bharat Nidhi) को चालू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए।
- डिजिटल भारत निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का स्थान लेगी।
- इस निधि के तहत एकत्र किए गए धन का उपयोग वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।
- इसका उपयोग कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत के लिए पायलट परियोजनाओं के लिए भी किया जाएगा।
- इस निधि के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए योगदान को सर्वप्रथम भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- केंद्र एक "प्रशासक" नियुक्त करेगा जो पात्र व्यक्तियों से "बोली" या आवेदन आमंत्रित करके " डिजिटल भारत निधि कार्यान्वयनकर्ताओं" का चयन करेगा।

'एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद' योजना'

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा 16 जुलाई 2024 को 'एक वैज्ञानिक-एक उत्पाद' कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:**कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना है।
- इस दौरान अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्मों को जारी किया गया।
- इन फसलों में 289 जलवायु प्रतिरोधी किस्में और 27 जैव-संवर्धित किस्में शामिल हैं।

साइंटिफिक डीप-ड्रिलिंग कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (BGRL) (कराड, महाराष्ट्र) द्वारा किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** पृथ्वी के क्रस्ट को 6 किमी की गहराई तक ड्रिल करना और वैज्ञानिक स्टडी और एनालिसिस करना है।
- इसके तहत महाराष्ट्र के कोयना-वारना क्षेत्र में एक्टिव फॉल्ट ज़ोन में जलाशय-के निर्माण के बाद नियमित रूप से महसूस होने वाले भूकंप झटकों के कारणों को समझा जा सकेगा।
- इसके तहत पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट के गहरे हिस्सों की स्टडी और एनालिसिस करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बोरहोल खोदा जाता है।
- यह वैज्ञानिकों को भूकंप का अध्ययन करने में मदद करता है तथा पृथ्वी के इतिहास, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों, जीवन रूपों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न आदि के बारे में समझ को बढ़ाता है।

प्रोजेक्ट अस्मिता (Project ASMITA)

- इसका पूरा नाम Augmenting Study Materials in Indian Languages through Translation and Academic Writing ((अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्धन) है।
- इसे शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 16 जुलाई को शुरू किया गया
- इसके तहत अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित की जाएगी।

- यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और मंत्रालय के तहत एक उच्चस्तरीय समिति भारतीय भाषा समिति का संयुक्त प्रयास है।
- इस परियोजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में भारतीय भाषाओं में अनुवाद और मूल पुस्तक लेखन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
- इसका लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भाषा में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित होंगी।
- इस परियोजना हेतु विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ तेरह नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है।

"बहुभाषा शब्दकोष"

- प्रोजेक्ट अस्मिता के अलावा **"बहुभाषा शब्दकोष"**भी लॉन्च किया गया यह भारतीय भाषाओं में सीखने को गति प्रदान करेगा और भारत की भाषा परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देगा।"
- यह शब्दकोष सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों और उनके अर्थों के लिए एकल-बिंदु संदर्भ है।
- यह शब्दकोष केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से विकसित किया जाएगा।
- यह शब्दकोष आईटी, उद्योग, अनुसंधान, शिक्षा जैसे विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में भारतीय शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के प्रयोग में मदद करेगा।

केन्द्रीय बजट 2024-25

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में 23 जुलाई 2024 को केन्द्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) पेश किया।
- निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वाँ केंद्रीय बजट पेश किया है। (मोरारजी देसाई: 6 बजट) ऐसा करने वाली करने वाली वह पहली केंद्रीय वित्त मंत्री बनी है।
- बजट में 4 मुख्य समुदायों-'गरीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बजट की मुख्य विषयवस्तु

- बजट की विषयवस्तु रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है।
- देश में 2 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा की गई है।
- इस वर्ष, शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।

बजट प्राथमिकताएं

- विकसित भारत हेतु निम्नलिखित 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है-

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन

- किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।
- अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी।
- 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को कवर करने के उद्देश्य से सरकार, राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगी।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल

- रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाओं को कार्यान्वित करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन और पहली बार रोजगार प्राप्त कर्मचारियों की पहचान पर ध्यान और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की सहायता पर आधारित होंगी।

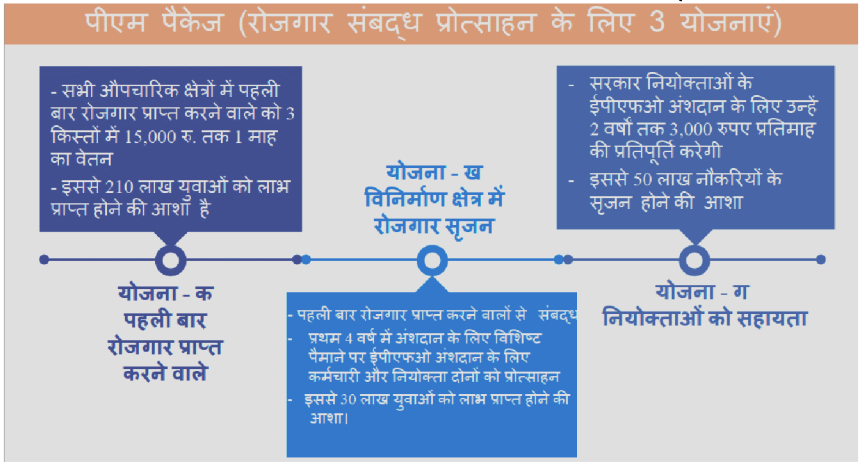

- सरकार उद्योग और क्रेचों के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों के गठन के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं की अधिक भागेदारी की भी सुविधा प्रदान करेगी।
- कौशल से जुड़े कार्यक्रमों का संदर्भ देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत चौथी योजना के तौर पर एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी।

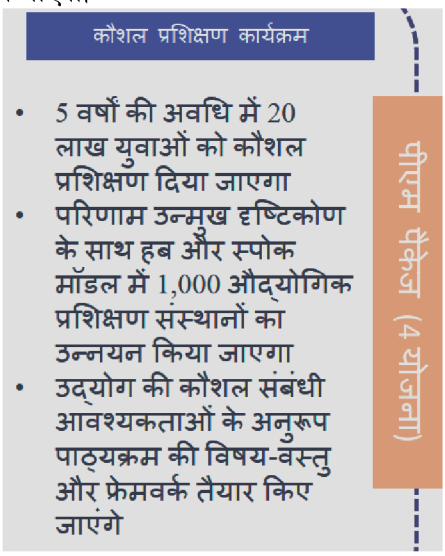

- सरकार से प्रोत्साहित कोष के माध्यम से 7.5 लाख तक की गारंटी के साथ ऋण की सुविधा के साथ मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा और इससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है।
- सरकारी योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत किसी भी लाभ के पात्र नहीं होने वाले युवाओं की सहायता के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

प्राथमिकता 3: समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

- सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी हिस्से के समग्र विकास के लिए एक पूर्वोदय योजना तैयार करेगी।
- इसमें विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचा और आर्थिक अवसर का सृजन शामिल होगा।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

- जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय परिवारों और 63,000 गांवों को शामिल करने वाले आकांक्षीय जिलों एवं 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ देने के लिए समग्र विकास के दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेगी।
- बैंकिंग सुविधाओं में विस्तार करते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में गठन किया जाएगा।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं

एमएसएमई के संवर्धन के लिए सहायता

- बजट में विशेष रूप से श्रम प्रोत्साहन विनिर्माण के साथ-साथ एमएसएमई और विनिर्माण पर खास ध्यान दिया गया है।
- 100 करोड़ तक के गारंटी कवर के साथ प्रत्येक आवेदक को एक पृथक रूप से तैयार स्वयं-वित्तीय गारंटी कोष प्रदान किया जाएगा, जबकि इसमें ऋण धनराशि और अधिक हो सकती है।
- इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय ऋण के लिए एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए अपनी अंदरूनी क्षमता को विकसित करेंगे। MSME के लिए बैंक ऋण में निरंतरता बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नए तंत्र की भी घोषणा की।

मुद्रा ऋण

- मुद्रा ऋणों की सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक किया जाएगा और यह सुविधा उन उद्यमियों के लिए होगी, जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत अपने पुराने ऋणों का सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है।

फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां

- एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप

- प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में, सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी।

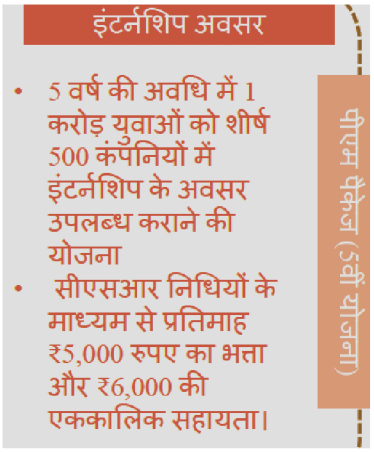

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

शहरी आवास

- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

- राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधनतथावित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे।

पीएम स्वनिधि

- रेहड़ी-पटरी वालों के जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण पीएम स्व निधि योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाटों' और स्ट्रीट फूड केंद्रों के विकास के लिए अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

- एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है।

प्राथमिकताः 7 अवसंरचना

- प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे।

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, 11,500 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।
- इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन, भू-स्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को भी सहायता प्रदान करेगी।

पर्यटन

- काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास।
- हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल।
- नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा का एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास।
- ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

- मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की शुरूआत करेंगे।
- अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

- अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि स्थापित की जाएगी।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

आर्थिक नीति फ्रेमवर्क

- सरकार आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएगी।

श्रम संबंधी सुधार

- सरकार श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के प्रावधान को सुगम बनाएगी जिनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी।
- ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा।
- उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की सुगमता बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।
- सरकार जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश

- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि-

(1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो।
(2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो।
(3) ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले।

एनपीएस वात्सल्य

- माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी।
- वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

पार्ट-B

- प्रत्यक्ष करों में केन्द्रीय बजट 2024-25 में अगले छह महीनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की व्यापक रूप से समीक्षा करने की बात की गई है।
- बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
- इसी प्रकार पेंशन धारकों के लिए फैमली पेंशन पर डिडक्शन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
- अब आकलनों को फिर से खुलने की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है अगर छुपाई गई आय 50 लाख रुपये से अधिक है। नई कर व्यवस्था दर संरचना में भी संशोधन किया गया है जिससे कि वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सके।

नई कर व्यवस्था दर संरचना

आय	कर प्रतिशत
0-3 लाख रुपये	शून्य
3-7 लाख रुपये	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये	20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- उद्यमशील भावना तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है।
- विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।
- बजट में निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- विवादों के समाधान तथा बैकलॉग के निपटान के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपील में लंबित कुछ खास आयकर विवादों के निवारण के लिए विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 का प्रस्ताव रखा गया है।
- उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय तथा ट्रिब्यूनलों में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर तथा सेवा कर से संबंधित अपील

दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमश: 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

- मुकदमेबाजी में कमी लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे को बढ़ाया जाएगा तथा ट्रांसफर प्राइसिंग आकलन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

बजट अनुमान 2024-25 (अनुमानित)

कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर)	32.07 लाख करोड़ रुपये
कुल व्यय (उधारियों को छोड़कर)	48.21 लाख करोड़ रुपये
निवल कर प्राप्तियां	25.83 लाख करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा (GDP का)	4.9 प्रतिशत
प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधारियां	14.01 लाख करोड़ रुपये
प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधारियां	11.63 लाख करोड़ रुपये

आर्थिक समीक्षा 2023-24

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई, 2024 को 'आर्थिक समीक्षा 2023-24' पेश की गई।
- **सकल घरेलू उत्पाद:** वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 6.5-7% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2% रही है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से तेजी से उबर गई, वित्त वर्ष 24 में इसकी वास्तविक जीडीपी कोविड-पूर्व, वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20% अधिक थी।
- **क्षेत्रों का योगदान:**वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7% थी।
- **चालू खाता घाटा(CAD):**वित्त वर्ष 24 के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% घाटे से बेहतर स्थिति है।
- **राजकोषीय घाटा:** वित्त वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर वित्त वर्ष 24 (2023-24) में जीडीपी के 5.6% पर है।
- **कुल कर संग्रह: इस**का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
- वित्त वर्ष 2024 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड रुपये रहा, जो साल दर साल आधार पर 28.2% की वृद्धि है ओर वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 2.8 गुना अधिक है।
- मार्च 2024 में सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां (GNPA) अनुपात घटकर 2.8% दर्ज किया गया, जोकि 12 वर्षों में बैंकों की सम्पत्ति गुणवत्ता में सबसे कम सुधार है।
- वित्त वर्ष 2024 में घरेलू मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में औसतन 6.7 प्रतिशत के बाद वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई है।
- GDP के एक अनुपात के रूप में बाह्य ऋण मार्च 2024 के अंत में 18.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहा।
- सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 17 गुणा की वृद्धि के साथ स्वीकृत पेटेंट की संख्या 1,03,057 हो गई।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2024 में भारत 39वें स्थान पर है।
- भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है।
- प्रचलित मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 18.2% है।
- वित्त वर्ष 2024 में विनिर्माण क्षेत्र 9.9 प्रतिशत की दर से बढा है, इसके अलावा निर्माण गतिविधियों में भी 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई।
- विनिर्माण क्षेत्र भारतीय औद्योगिक सेक्टर के अग्रणी क्षेत्रों में से एक रहा, जिसने पिछले दशक में 5.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर अर्जित कीगई।
- विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की हिस्सेदारी 35.4% रही।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना MSME उद्यमों हेतु सहायक सिद्ध हुई।
- 'एक जिला, एक उत्पाद' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों को यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

MSMEs की भूमिका:

- सर्वेक्षण के अनुसार MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% का योगदान करते हैं और देश की 11 करोड़ आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं।
- केंद्र सरकार MSMEs सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के आवंटन जैसी पहलों के माध्यम से MSME क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दे रही है।

सेवा क्षेत्र:

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सेवा क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत है।

- सेवा निर्यात ने स्थिर गति बनाए रखी है और वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात का 44% हिस्सा था।
- भारत सेवा निर्यात में पांचवें स्थान पर है, अन्य देश यूरोपीय संघ (इंट्रा-ईयू व्यापार को छोड़कर), संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन हैं।
- वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 6.0 प्रतिशत हो गई।
- वित्त वर्ष 2024 में सेवाओं में भारत का निर्यात उच्च स्तर पर पहुंचकर 341.1 बिलियन दर्ज रहा।
- वित्त वर्ष 2024 में निर्यात (वस्तु एवं सेवाएं) 0.15% बढ़ा, जबकि कुल आयातों में 4.9% गिरावट दर्ज की गई।

महिला श्रम बल भागीदारी दर:

- शिक्षा और कौशल विकास तक पहुँच में वृद्धि के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के लिए अन्य पहलों ने राष्ट्र के विकास और प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2017-2018 में 23.3% से बढ़कर 2022-2023 में 37% हो गई।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने मई 2024 तक 52.3 करोड़ बैंक खाते खोलने में मदद की है, जिनमें से 55.6 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं।

सामाजिक सेवाओं पर व्यय:

- सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% से बढ़कर 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 7.8% हो गया है।
- इससे बहुआयामी गरीबी में भारी गिरावट आई है तथा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) 2015-16 में 0.117 से घटकर 2019-21 में 0.066 रह गया है।
- सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न पहलों के चलते असमानता में कमी आई है। पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए गिनी गुणांक 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के लिए 0.363 से घटकर 0.314 हो गया है।

स्वास्थ्य व्यय:

- स्वास्थ्य व्यय2017-18 से 2023-24 की अवधि में स्वास्थ्य व्यय 1.4% से बढ़कर 1.9% हो गया है।
- कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2023-24 (BE) में 26% तक बढ़ गया, जिसमें से स्वास्थ्य पर व्यय 6.5% था।

4. अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

SCO का 24वां शिखर सम्मेलन

- शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन (SCO Summit) 2024 कज़ाकिस्तान के अस्ताना में 3-4 जुलाई को आयोजित किया गया।
- सम्मेलन के दौरान SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक हुई।
- इस शिखर बैठक की मेजबानी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव ने की।
- इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित 16 विश्व नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया।
- शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने किया।
- सम्मेलन के दौरान यूरेशियाई देश बेलारूस को SCO के 10वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- SCO शिखर सम्मेलन 2023 में ईरान को 9वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित की जाएगी।

शंघाई सहयोग संगठन

परिचय	भारत के लिए SCO का महत्व
• अंतर सरकारी संगठन, स्थापना:2001 में • रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा शंघाई में स्थापित किया गया • वर्ष2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बने। • यह समूह अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। • SCO के स्थायी सदस्य (10 देश): कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस • मुख्यालय: बीजिंग (चीन)	• यह मंच मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के अपने दायरे को बढ़ाता है। • यह सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ संचार बनाने मे सहायक है। • इसका रीजनल एंटी-टेरोरिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) आतंकवादी गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करता है। • इसमें भारत की प्राथमिकताएँ प्रधानमंत्री के 'सिक्योर' SCO (SECURE SCO) से प्रेरित हैं। सिक्योर का तात्पर्य सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण संरक्षण से है।

22वीं वार्षिक भारत-रूस शिखर बैठक

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे।
- यात्रा के पहले चरण में, वे रुस गए थे जहां राजधानी मास्को में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए।
- तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली विदेशी द्विपक्षीय यात्रा थी।
- यह बैठक मॉस्को के क्रेमलिन में आयोजित की गई थी।
- द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-रूस स्थायी और विस्तारित साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त घोषणा जारी की।
- दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 9 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- संयुक्त घोषणा में भारत-रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना;
- 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हासिल करना शामिल है।
- रूस उर्वरक आपूर्ति के लिए भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करेगा।
- दोनों देश चेन्नई-व्लादिवोस्तोक (पूर्वी समुद्री) कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को लागू करने और उत्तरी समुद्री मार्ग की क्षमता का पता लगाने के लिए काम करेंगे।
- परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग जारी रहेगा।
- Note: रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है।
- यात्रा के दौरान, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' (Order of St. Andrew The Apostle) से सम्मानित किया।
- Note: इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 9-10 जुलाई 2024 को ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर थे।
- पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी।

मुख्य बिन्दु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वान डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।
- दोनों नेताओं की बैठक के बाद, 'उन्नत भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी' शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया गया।
- संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और ऑस्ट्रिया अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कुल सदस्यता 100 है। पराग्वे गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश है।
- प्रधान मोदी की यह आधिकारिक यात्रा उस समय हुई है जब भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

ऑस्ट्रिया

- ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित स्थल से घिरा हुआ देश है।
- इसकी राजधानी वियना है। इसकी भाषा जर्मन और मुद्रा यूरो है।
- ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का सदस्य है।
- ऑस्ट्रिया के उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य से, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में स्लोवाकिया और इटली और पश्चिम में स्विटजरलैंड और लीश्टेनश्टाइन है।

बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक

- बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 11-12 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली मे आयोजित की गई।
- इसमें सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश, लोगों से लोगों के बीच संपर्क आदि के क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई।
- नोट: बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी।

बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक

- बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी बैठक 27 जुलाई को म्यांमार के नाएप्यीडॉ में आयोजित की गई।
- इसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने किया।
- बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
- बिम्सटेक (BIMSTEC) की स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय समूह के रूप में की गई थी।
- BIMSTEC का पूरा नाम Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation है।
- भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार इसके सात सदस्य हैं।
- बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है।

केंद्रीय मंत्रिमंडलने भारत को BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction: BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है।
- यह निर्णय राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सस्टेनेबल उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 'खुला समुद्र' या "हाई सी" के रूप में कहे जाने वाले "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र" ग्लोबल कॉमन महासागर हैं अर्थात इन पर किसी का अधिकार नहीं है और पूरे विश्व की साझी सम्पदा है।
- ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध उद्देश्यों जैसे नेविगेशन, ओवरफ़्लाइट, सबमरीन केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए सभी के लिए खुले हैं।
- भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।

BBNJ समझौता

- BBNJ समझौता, या 'खुलासमुद्र संधि', (High Seas Treaty) समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- BBNJ समझौते पर मार्च 2023 में सहमति बनी थी।
- अनुसमर्थन, स्वीकृति, मंजूरी के 120 दिन बाद लागू होने के बाद यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय संधि होगी।
- जून 2024 तक, 91 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और आठ पक्षों ने इसका अनुसमर्थन किया है।
- इसका उद्देश्य खुला समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है।
- समझौता के पक्षकार देश हाई-सी से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित कर सकते हैं।

- BBNJ समझौता UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। दो अन्य समझौते हैं: 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता और 1995 संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता।

UNCLOS

- UNCLOS को 10 दिसंबर, 1982 को अपनाया गया था और यह 16 नवंबर, 1994 को लागू हुआ।
- यह समुद्र के पर्यावरण संरक्षण और समुद्री सीमाओं, समुद्री संसाधनों के अधिकारों और विवाद समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।

जैविक उत्पादों पर भारत-ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता

- भारत और ताइवान के बीच 8 जुलाई, 2024 से चाय और चिकित्सा उपयोग वाले पौधों सहित जैविक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता (MRA) लागू हुआ।
- पारस्परिक मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreement: MRA) से दोहरे सर्टिफिकेशन से बचेंगे और बचाकर जैविक उत्पादों के निर्यात को आसानी होगी।
- यह समझौता चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- MRA के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी हैं।

भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरीशस में खुला

- केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 18 जुलाई 2024 को मॉरीशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया।
- भारत-मॉरीशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी, भारत में निर्मित दवाओं की आपूर्ति करेगी।
- मॉरीशस के ग्रैंड बोइस में भारतीय अनुदान सहायता से मेडिक्लिनिक परियोजना का उद्घाटन भी किया गया।
- इससे ग्रैंड बोइस क्षेत्र के 16,000 लोगों को द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा मिलेगी।
- मॉरीशस पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है।
- इस द्वीप की 1.2 मिलियन की आबादी में भारतीय मूल के लोग लगभग 70% हैं।

आइवरी कोस्ट UN वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ

- हाल ही में आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया।
- आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला वह 10वाँ अफ्रीकी देश है।
- यह अब 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन का 53वाँ पक्षकार (देश) है।
- UN वाटर कन्वेंशन को "ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन" के नाम से भी जाना जाता है।
- इसे 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ।
- यह कन्वेंशन साझा जल संसाधनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि (legally binding) है।
- इसके तहत पक्षकारों को ट्रांसबाउंड्री प्रभाव को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने, ट्रांसबाउंड्री जल का उचित और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है।
- संशोधन प्रक्रिया के बाद, मार्च 2016 से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं।
- नोट: भारत इस कन्वेंशन का पक्षकार नहीं है।

रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र

- यह भारत और म्यांमार के बीच व्यापार निपटान तंत्र है
- इसके तहत भारत से म्यांमार को 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दालों के निर्यात का पहला लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाएगा।
- सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार ने विशेष रुपया वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) के तहत भुगतान प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए है।

वोस्ट्रो खाता (vostro account)

- वोस्ट्रो खाता (vostro account) एक ऐसा खाता है जो एक कॉरेसपोंडेंट बैंक किसी अन्य बैंक की ओर से अपने यहां रखता है।
- ये खाते कॉरेसपोंडेंट बैंकिंग का एक अनिवार्य पहलू हैं जिसमें जमा राशि रखने वाला बैंक किसी विदेशी बैंक के खाते के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसका प्रबंधन करता है।
- इन खातों का उपयोग विदेशी मुद्रा विनिमय या विदेशी व्यापार के निपटान के लिए किया जाता है।

चागोस द्वीपसमूह विवाद

- हाल ही में भारत ने चागोस द्वीपसमूह विवाद में मॉरीशस का समर्थन किया
- चागोस द्वीपसमूह सात एटोल का एक समूह है जिसमें डिएगो गार्सिया द्वीप भी शामिल है, जिस पर अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थित है।
- मॉरीशस द्वारा दावा किए जाने के बावजूद, चागोस द्वीपसमूह यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है और डिएगो गार्सिया को 1960 के दशक में अमेरिका को पट्टे पर दिया गया था।

- चागोस द्वीपसमूह में हिंद महासागर के मध्य में लगभग 58 छोटे, बहुत निचले द्वीप शामिल हैं।
- फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1965 में मॉरीशस से चागोस द्वीपसमूह को अलग करने के कानूनी विवाद पर एक सलाहकार राय जारी की।
- इसमे न्यायालय ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम छह महीने के भीतर बिना शर्त अपने औपनिवेशिक प्रशासन को क्षेत्र से वापस ले ले और इसे मॉरीशस को सौंप दे।

माशको पीरो जनजाति

- हाल ही में सर्वाइवल इंटरनेशनल द्वारा कॉन्टैक्टलेस जनजाति माशको पीरो आदिवासियों (Mashco Piro) की दुर्लभ तस्वीरें जारी की गई।
- माशको पीरो जनजाति अमेजन और दक्षिण-पूर्वी पेरू के जंगलों में रहते हैं।
- माशको पीरोकी संख्या संभवतः 750 से अधिक है, ऐसी जनजातियों में सबसे बड़ी मानी जाती है।
- ये खानाबदोश शिकारी-संग्राहक ब्राजील और बोलीविया के साथ पेरू की सीमा के करीब माद्रे डी डिओस क्षेत्र (Madre de Dios Region) के अमेजन जंगलों में रहते हैं।
- पेरू की सरकार ने माशको पीरो के साथ सभी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि आबादी में कोई बीमारी फैल सकती है, जिसके लिए उनके पास कोई प्रतिरक्षा नहीं है।
- यह जनजाति बहुत ही एकांतप्रिय है, केवल कभी-कभी मूल निवासियों से संपर्क करती है।

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

SEBEX 2

- भारत ने "SEBEX 2" नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु विस्फोटक बनाया है।
- यह विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलुइन (TNT) की तुलना में दोगुने (2.01) से भी अधिक घातक है।
- इसका इसे भारतीय नौसेना ने सफल परीक्षण कर प्रमाणित किया है।
- इसे नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया।
- SEBEX 2 हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव (HMX) संरचना का उपयोग करता है।
- यह फार्मूलेशन वारहेड्स, हवाई बमों, तोप के गोले और अन्य युद्ध सामग्री की मारक क्षमता को बढ़ा देता है।
- सेबेक्स 2 बिना वजन बढ़ाए बम, गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है।
- SEBEX 2, SITBEX 1 और SIMEX 4 सैन्य प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं।
- नोट: भारत में अभी इस्तेमाल किया जा रहा सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक ब्रह्मोस मिसाइल के वारहेड में इस्तेमाल हो रहा है।

SITBEX 1

- SITBEX 1 एक थर्मोबैरिक विस्फोटक है जो अपनी विस्तारित विस्फोट अवधि और इंटेंस हीट उत्पादन के लिए जाना जाता है।
- यह दुश्मन के बंकरों, सुरंगों और किलेबंद ठिकानों को ध्वस्त करने में अत्यधिक प्रभावी है।

स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण

- भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर (Zorawar) का 6 जुलाई 2024 को अनावरण किया गया।
- इस टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ मिलकर प्रमुख इंटीग्रेटर के रूप में विकसित किया है।
- यह टैंक वर्तमान में एक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है।
- यह टैंक पृथ्वी पर सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में संचालन करने में सक्षम है, अर्थात उत्तरी सीमा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी यह काम कर सकता है।
- इसे पहाड़ों में तेजी से तैनाती और कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस टैंक को अगस्त 2025 तक यूजर्स ट्रायल के लिए सेना को सौंपा।
- पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ गलवान संघर्ष के बाद हल्के टैंकों की आवश्यकता महसूस की गई थी।
- प्रोजेक्ट ज़ोरावर के तहत भारतीय सेनाने लगभग 25 टन वजन वाले 350 हल्के टैंक शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

रुद्रम-1 का सफल परीक्षण

- यह भारत की पहली स्वदेशी विकिरण-रोधी मिसाइल(Anti-Radiation Missile)है।
- इसे भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है।
- रुद्रम-1 (Rudram-1) को IAF के सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया गया है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है।
- इसमिसाइल में INS-GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों को सटीक रूप से हिट कर सकती है।
- यह सटीकता शत्रु वायु रक्षा दमन (SEAD) अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे लंबी दूरी से दुश्मन के रडार और संचार स्थलों को नष्ट किया जा सकता है।

DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफल उड़ान परीक्षण किया

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 24 जुलाई, 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली चरण-II का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।
- टारगेट मिसाइल को LC-IV धामरा से 1620 बजे लॉन्च किया गया, जो कि शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल की कॉपी थी।
- इसे जमीन और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली रडार द्वारा पता लगाया गया और AD इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय किया गया।
- चरण-II की AD एंडो-वायुमंडलीय मिसाइल को ITR, चांदीपुर (ओडिशा) से लॉन्च किया गया।
- इस परीक्षण ने 5,000 किमी श्रेणी की शत्रु बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने हेतुदेश की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित किया है।
- चरण-II AD एंडो-वायुमंडलीय मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित दो चरणों वाली ठोस प्रणोदित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है
- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का चरण 1, जो 2,000 किमी की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, जिसे पहले ही तैनात किया जा चुका है।

एयरबस भारत में निर्मित पहला H-1252026 तक तैयार करेगा

- एयरबस ने भारतीय साझेदार टाटा के साथघोषणा की कि वह H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए अंतिम असेंबली लाइन (FAL) बनाने का काम शुरू करेगा।
- एयरबस ने विनिर्माण इकाइयों हेतु अब तक 8 स्थानों का चयन किया है।
- इसके तहत पहला मेड-इन-इंडिया हेलीकॉप्टर 2026 मेंआपूर्ति की जाएगी।
- भारत में अंतिम असेंबली लाइन पर, सालाना 10 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया जाएगा। भविष्य में, यह संख्या 20, 30 या 50 तक बढ़ सकती है।
- इसके अलावा कंपनी हेलीकॉप्टरों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
- भारत के हेलीकॉप्टर MRO परिचालन का समर्थन करने हेतु, एयरबस और इंडमेर ने दिसंबर 2023 में साझेदारी की और मुंबई, नई दिल्ली और नागपुर में एयरबस हेलीकॉप्टरों के लिए सेवाएं दी जा रही है।

'त्रिपुट' युद्धपोत

- भारतीय नौसेना के लिए रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर दो अत्याधुनिक जंगी जहाजों (फ्रिगेट) में से पहला जहाज 23 जुलाई 2024 को GSL, गोवा में लॉन्च किया गया।
- इस जंगी जहाज का नाम "त्रिपुट (Triput)"रखा गया है, जो शक्तिशाली तीर के नाम पर है।
- यह भारतीय नौसेना की अदम्य भावना और दूर और गहराई तक वार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा निर्मित किया गया है।
- **नोट:** भारत ने अक्टूबर 2016 में रूस से चार फ्रिगेट का अनुबंध किया था, जिनमें से दो रूस में और दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाने थे।
- त्रिपुट श्रेणी के फ्रिगेट 125 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े हैं, जिनका विस्थापन लगभग 3,600 टन है और इनकी अधिकतम गति 28 समुद्री मील है।

आदित्य-L1 ने L1 पॉइंट के चारों ओर अपनी पहली हेलो ऑर्बिट पूरी की

- भारत के पहले सौर मिशन, आदित्य-L1 (Aditya-L1) अंतरिक्ष यान ने 2 जुलाई 2024 को सूर्य-पृथ्वी L1 पॉइंट के चारों ओर अपनी पहली हेलो ऑर्बिट पूरी की है।
- हेलो ऑर्बिट में आदित्य-L1 अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लगते हैं।
- आदित्य-L1 मिशन, जो लैग्रेंजियन पॉइन्ट L1 पर एक भारतीय सौर वेधशाला है, 2 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, और 6 जनवरी, 2024 को अपने टारगेट हेलो ऑर्बिट में प्रवेश किया।
- आदित्य-L1 अंतरिक्ष यान की कक्षा एक आवधिक हेलो ऑर्बिट है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर लगातार गतिमान सूर्य-पृथ्वी रेखा पर स्थित है।
- हेलो ऑर्बिट L1 पर एक आवधिक, त्रि-आयामी कक्षा है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और एक अंतरिक्ष यान शामिल है।
- यह विशिष्ट हेलो ऑर्बिट 5 साल के मिशन जीवनकाल को सुनिश्चित करने के लिए चुनी गई है, इससे सूर्य का निरंतर, अबाधित दृश्य प्राप्त होता है।

CHAPEA प्रोजेक्ट

- इसका पूरा नाम Crew Health and Performance Exploration Analog है।
- हाल ही में, नासा द्वारा संचालित CHAPEA प्रोजेक्ट के चार स्वयंसेवी क्रू सदस्य मंगल ग्रह जैसे वातावरण में रहने हेतु तैयार आवास में 1 वर्ष रहने के बाद बाहर आए।
- यह अंतरिक्ष में खोज के लिए मंगल ग्रह की चुनौतियों को समझने के लिए तीन नियोजित सिमुलेशन में से पहला था।
- CHAPEAएनालॉग मिशनों की एक सीरीज है जो मंगल की सतह जैसे माहौल में साल भर रहने का अनुकरण करती है।
- प्रत्येक मिशन में चार चालक दल के सदस्य शामिल होंगे जो मंगल ड्यून अल्फा में रहेंगे, जो एक अलग 1,700 वर्ग फुट का आवास है।
- मार्स ड्यून अल्फा के नाम से जानी जाने वाली यह 3D प्रिंटेड संरचना, टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में स्थित है।

विश्व का पहला ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट

- विश्व के पहले ड्यूल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन चीन के काजो गांसु प्रांत में किया गया है।
- यह प्लांट ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हेतु एक नवाचार डिजाइन का उपयोग करता है।
- इस प्लांट में 200-200 मीटर के दो ऊंचे टॉवर हैं, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर लगभग 30,000 मिरर हैं जो टावरों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए ओवरलैपिंग सर्कल बनाते हैं।
- यह ड्यूल टावर संरचना एक महत्वपूर्ण इनोवेशन है जो इस प्लांट को पारंपरिक सोलर थर्मल केंद्रों से अलग करता है।
- केंद्रित सूर्य का प्रकाश टावरों के अंदर पानी को गर्म करता है, जिससे भाप उत्पन्न होती है जो टर्बाइनों को बिजली बनाने के लिए प्रेरित करती है।
- पारंपरिक थर्मल पावर प्लांट के विपरीत, इस डिज़ाइन में पिघले हुए नमक का भंडारण शामिल है, जो एक थर्मल बैटरी के रूप में कार्य करता है।
- पिघला हुआ नमक दिन के दौरान एकत्रित अतिरिक्त गर्मी को बरकरार रखता है और रात में इसे उत्सर्जित करता है, जिससे प्लांट लगातार बिजली पैदा कर सकता है।
- इस प्लांट में उपयोग किए जाने वाले मिरर विशेष सामग्रियों से

बने होते हैं जो उल्लेखनीय 94% परावर्तन दक्षता प्राप्त कर सकते हैं।

- मिरर को सूर्य की गति को स्वतः ट्रैक करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो सुबह में पूर्वी टॉवर पर किरणों को केंद्रित करते हैं और दोपहर में पश्चिम की ओर समायोजित होते हैं।

डार्क ऑक्सीजन

- हाल में वैज्ञानिकों ने महासागरीय तल (Ocean Floor) पर "डार्क ऑक्सीजन" (Dark Oxygen) की खोज की है।
- इसका उत्पादन महासागरीय तल पर बिखरे पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स धातु के ढेरों से होता है।
- हालिया रिसर्च अनुसार प्रशांत महासागर के क्लेरियन-क्लिपरटन ज़ोन (CCZ) के समुद्र तल पर समुद्र की सतह से 4,000 मीटर नीचे बिखरे खनिज भंडार से ऑक्सीजन उत्पादित होती है।
- क्लेरियन-क्लिपरटन ज़ोन में, कोयले जैसी खनिज चट्टानें हैं, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहा जाता है, जिनमें आमतौर पर मैंगनीज और लोहा होता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार ये नोड्यूल प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) की प्रक्रिया के बिना ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
- समुद्र में इतनी गहराई पर, जहाँ कोई सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन, धातु के "नोड्यूल्स" द्वारा उत्पादित होती है।
- ये धातु समुद्री जल (H2O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है।

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएनसेफेलाइटिस (PAM)

- हाल ही मेंकेरल में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएनसेफेलाइटिस (primary amoebic meningoencephalitis: PAM) के कुल 4 मामले सामने आए हैं।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार, PAM नेगलेरिया फाउलेरी के संक्रमण से होता है।
- नेगलेरिया फाउलेरी एक अमीबा है जो झीलों, तालाबों और नदियों जैसे गर्म फ्रेश वाटर के वातावरण में रहता है।
- दुर्लभ परिस्थितियों में, यह खराब रखरखाव वाले तालाब/झीलों/स्विमिंग पूल में भी रह सकता है।
- यह एककोशिकीय जीव है और इसे 'दिमाग खाने वाला अमीबा' कहा जाता है।
- यह मस्तिष्क को संक्रमित कर सकता है और इसके ऊतकों को नष्ट कर सकता है।
- इसके संक्रमण के मामले दुर्लभ हैं, लेकिन ये जानलेवा हैं और इनसे संक्रमित 97% लोगों के लिए बचना मुश्किल है।
- इसका संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब लोग गर्मियों के दौरान झीलों, तालाबों या नदियों में तैरने जाते हैं।
- अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुँचता है, जहाँ यह मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है और सूजन का कारण बनता है।
- यह संक्रामक नहीं है अर्थात यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है।

ओरोपोच वायरस

- ओरोपोच वायरस से विश्व में किसी व्यक्ति की मौत का पहला मामला ब्राजील में दर्ज हुआ है।
- ब्राजील में ओरोपोच बुखार से दो महिलाओं की मौत हो गई।
- ओरोपोच बुखार (Oropouche fever) से होने वाली मौत में डेंगू के समान ही लक्षण दिखे।
- ओरोपोच वायरस (Oropouche virus) का पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो में पता चला था।
- ओरोपोच बुखार ओरोपोच वायरस के कारण होता है, जो कि क्यूलिकोइड्स पैरेंसिस मिज के काटने से सबसे अधिक फैलता है।
- रोग के लक्षण डेंगू के समान होते हैं और आमतौर पर काटने के चार से आठ दिनों के बीच शुरू होते हैं।
- इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, दर्द, ठंड लगना, जोड़ों में अकड़न और कभी-कभी मतली और उल्टी शामिल होती है।
- इसके अधिकांश रोगी लगभग सात दिनों में ठीक हो जाते हैं।
- WHO के अनुसार, इसके गंभीर मामले दुर्लभ हैं। इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट टीका या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है।

चांदीपुरा वायरस

- हाल ही में गुजरात के साबरकांठा जिले में, चांदीपुरा वायरस (Chandipura virus) के संदिग्ध संक्रमण के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई।
- चांदीपुरा वायरस एक रेयर और घातक रोगज़नक़ है जो बुखार, फ्लू जैसे लक्षण और तीव्र इंसेफेलाइटिस (मस्तिष्क की सूजन) का कारण बनता है।
- इसके फैलने का कारण CHPV रबडो विरिडे फैमिली का एक वायरस है, जिसमें रेबीज का कारण बनने वाले लाइसावायरस जैसे अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
- सैंडफ्लाइज़ की कई प्रजातियां जैसे फ़्लेबोटोमाइन सैंडफ़्लाइज़ और फ़्लेबोटोमस पपाटासी, और कुछ मच्छर प्रजातियां जैसे एडीज एजिप्टी को (जो डेंगू का वाहक भी है)CHPV का वाहक माना जाता है।
- CHPV संक्रमण सैंडफ्लाइज़ नाम के मच्छर के काटने से होता है। इसकी चपेट में आने पर शुरू में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते है।
- इस संक्रमण की चपेट में आकर तेज बुखार (104 तक) हो सकता है, डायरिया, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसी परेशानी होती है। इसके बाद यह वायरस सेंसोरियम (sensorium) और एन्सेफलाइटिस encephalitis में बदल सकता है। इसके दूसरे लक्षणों में सांस लेने में दिक्कत होना, ब्लीडिंग और

एनीमिया जैसे लक्षणों को भी देखा गया है।

- इस वायरस के कारण होने वाला ये संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच सकता है जिससे एन्सेफलाइटिस (दिमाग के टिशू में सूजन होना) हो सकता है।
- इसका संक्रमण मुख्यतः बच्चों (15 साल से कम उम्र) में होता है।
- इस वायरस की पहचान पहली बार 1965 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के चांदीपुरा गांव से हुई थी।
- इस वायरस से बचाव का अभी कोई टीका नहीं बना है लेकिन लक्षणों को देखते हुए इस बीमारी का इलाज किया जा रहा है।

निपाह वायरस (Nipah Virus)

- हाल ही में केरल के मलप्पुरम जिले के पांडिक्कड़ में 15 वर्षीय एक लड़के की 21 जुलाई को निपाह वायरस (Nipah virus) के संक्रमण से मौत हो गई।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन निपाह वायरस (NiV) को एक जूनोटिक वायरस के रूप में वर्णित करता है। अर्थात यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और दूषित भोजन या संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
- फ्रूट बैट (Pteropus bat species) निपाह वायरस के कॉमन होस्ट हैं, और मनुष्य गलती से चमगादड़ से दूषित फल खाने से संक्रमित हो सकते हैं।
- इसके संक्रमण मामले में मृत्यु दर 40% से 75% होने का अनुमान है।
- निपाह वायरस जानवरों (जैसे चमगादड़ या सूअर) या दूषित खाद्य पदार्थों से मनुष्यों में फैल सकता है और सीधे मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है।
- इस वायरस से संक्रमित लोगों या जानवरों के लिए कोई उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।
- निपाह वायरस की पहचान सबसे पहले 1999 में मलेशिया में सुअर पालने वाले किसानों में एक प्रकोप के दौरान हुई थी।

R21/Matrix-Mटीका

- यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड-द्वारा विकसित मलेरिया की वैक्सीन (विश्व की दूसरी) है।
- आइवरी कोस्ट इस टीके का उपयोग करने वाला विश्व कापहला देश बन गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में अफ्रीका में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस टीके के इस्तेमाल की सिफारिश की थी।
- मॉस्किरिक्स (Mosquirix या RTS,S/ASO1 या RTS.S) विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन है।
- इसे GSK Plc और उसके भागीदारों द्वारा विकसित किया गया।
- इस टीकाकरण में मलेरिया के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ाने में मदद करने के लिए नोवावैक्स इंक द्वारा विकसित एक बूस्टर का उपयोग किया जाता है।

लद्दाख: रॉक वार्निश परतों में मैग्नेटोफॉसिल्स की खोज

- शोधकर्ताओं ने लद्दाख में रॉक वार्निश परतों में मैग्नेटोफॉसिल्स (Magnetofossils) की खोज की हैं।
- लद्दाख को "भारत के ठंडे रेगिस्तान" के रूप में जाना जाता है, यहाँ हाई अल्ट्रा वॉयलेट विकिरण, महत्वपूर्ण तापमान भिन्नता और सीमित जल उपलब्धता जैसी चरम जलवायु परिस्थितियों का अनुभव करता है, जो इसे मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त स्थलीय एनालॉग बनाता है।

मैग्नेटोफॉसिल्स

- मैग्नेटोफॉसिल्स मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष हैं।
- मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खुद को व्यवस्थित करते हैं।
- ये जीव चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करके उन स्थानों तक पहुँचते हैं जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है।

अभ्यास मैत्री (Exercise MAITREE) 2024

- यह भारत-थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- इसका आयोजन 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में किया गया।
- इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास 2024

- यह भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- इसके 16वें संस्करण का आयोजनउमरोई (मेघालय) में 03 से 16 जुलाई 2024 तककिया गया।
- यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।

'इंटरैक्शन-2024'

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का पहला संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास है।
- इसमें लाइव अभ्यास और "आतंकवादी समूहों के उन्मूलन" जैसे विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसका आयोजन चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में आयोजित किया गया।
- SCO अपने क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी फ्रेमवर्क (Regional Anti-Terrorism Structure: RATS) के साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है।

पिच ब्लैक अभ्यास 2024

- यह द्विवार्षिक, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
- यह अभ्यास 12 जुलाई से 02 अगस्त तक डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) में आयोजित कियागया।
- इसमें भारतीय वायुसेना से भाग लिया।
- यह अभ्यास अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और अनुभव वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बड़े फोर्स की तैनाती वाले युद्ध पर केंद्रित है।

खान क्वेस्ट अभ्यास 2024

- यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है।
- इसमें भारतीय सेना का एक दल भाग ले रहा है।
- यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित हो रहा है।
- यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में यूएसए और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ था।
- इसके बाद, वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में बदल गया।

6. खेल

पेरिस ओलंपिक 2024

- पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जा रहा है।
- 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण है।
- पेरिस 2024 का शुभंकर "फ्रीजियन कैप" हैं।
- भारत की पीवी सिंधु (बैडमिंटन) और अचंता शरत कमल (टेबल टेनिस) ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया।
- पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय दल में 16 खेल विधाओं में 70 पुरुषों और 47 महिलाओं सहित 117 एथलीट शामिल हो रहे है।
- पेरिस ने 1900 और 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी
- पेरिस लंदन के बाद तीन बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बना है।
- पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।
- मनु भाकर निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
- इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता।
- मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है।
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में, ब्रिटिश-भारतीय एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ और 200 मीटर बाधा दौड़ दोनों में रजत पदक जीते थे।
- मनु भाकर पीवी सिंधु के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला एथलीट बनी हैं।
- पहले ओलंपिक खेल (modern Olympic Games) प्राचीन ओलंपिक के जन्मस्थान एथेंस (ग्रीस) में अप्रैल 1896 में हुए थे।
- 1920 में एंटवर्प ओलम्पिक खेलों में भारत ने अपना पहला आधिकारिक दल भेजा।
- हेलसिंकी 1952 ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
- बीजिंग 2008 ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता।
- टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते।

चीन ने पेरिस ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता

- 2024 पेरिस ओलंपिक में चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता।
- चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- हुआंग युटिंग और शेंग लिहाओ की चीनी जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी किम जिहयोन और पार्क हाजुन को 16-12 से हराया।

विंबलडन चैंपियनशिप 2024:

- विम्बलडन 2024 टेनिस प्रतियोगिता (Wimbledon Tennis Championships) 24 जून से 14 जुलाई तक लंदन में खेला गया.

श्रेणी	विजेता	उपविजेता-
पुरुष एकल	**कार्लोस अलकराज (स्पेन)**	नोवाक जोकोविच (सर्बिया)
महिला एकल	**बारबोरा क्रेजिसिकोवा (गणराज्य चेक)**	जैस्मिन पाओलिनी (इटली)
पुरुष युगल	हैरी हेलोवारा (फिनलैंड) और हेरी पैटन (ब्रिटेन)	मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन (दोनों ऑस्ट्रेलियाई)
महिला युगल	टेलर टाउनसेंड (यूएसए) और कैट्रेनिया सिनियाकोवा (चेक गणराज्य)	गैब्रिएला डाब्रोवस्की (कनाडा) और एरिन राउटलिफ़ (न्यूज़ीलैंड)
मिश्रित युगल	जान ज़िलिंस्क (पोलैंड) हसीह सु-वेई (ताइवान)	सैंटियागो गैंज़ालेज़ और गिउलिआना ओल्मोस (दोनों मेक्सिको के)

- अल्काराज ने अब तक चार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं. वे तीनों तरह के कोर्ट घास, क्ले और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंडस्लैम ट्रॉफी जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं।
- अल्काराज ने 2024 में फ्रेंच ओपन, 2022 में यूएस ओपन और 2023 और 2024 में विंबलडन खिताब जीता है।
- नोवाक जोकोविच के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड है. (24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब)
- चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिसिकोवा अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता।
- क्रेजिसिकोवा ने इससे पहले 2021 फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता था।

विम्बलडन

- यह दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है।
- पहली बार विम्बलडन का आयोजन 1877 में किया गया था।
- यह चार ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स में से एक है। अन्य ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन हैं। यह एकमात्र प्रतियोगिता है, जिसे आज भी खेल की मूल सतह, घास, पर खेला जाता है।

स्पेन 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बना

- स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप (EURO Cup) 2024 फुटबॉल का खिताब जीत लिया। बर्लिन में 14 जुलाई को फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया।
- यह यूरो कप का 17वां संस्करण था
- इसके साथ ही स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम (ला रोजा के नाम से भी प्रसिद्ध)सबसे ज्यादा बार यूरो कप का टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है।

यूरो कप

- UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैम्पियनशिप को यूरो कप के नाम से जाना जाता है।
- इसका आयोजन यूरोपीय फुटबॉल शासी निकाय यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन (यूईएफए) द्वारा किया जाता है।

अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब जीता

- अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका (Copa America title) फुटबॉल 2024 का खिताब जीत लिया है।
- 15 जुलाई 2024 को अमेरिका के मियामी में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया
- यह कोपा अमेरिका का 48वां संस्करण था।

कोपा अमेरिका

- कोपा अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है
- इसे1916 में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल शासी निकाय द्वारा शुरू किया गया था।
- वर्तमान में प्रतियोगिता में दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई देशों के सभी देश इसमे भाग लेते हैं।
- कोपा अमेरिका प्रतियोगिता के इतिहास में अर्जेंटीना सबसे सफल टीम है।

ध्रुव सितवाला ने तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता

- ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जीती।
- इसका आयोजन 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था।

सबीरा हारिस ने शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता

- भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेटो में ISSF जूनियर विश्व कप में महिला ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
- अमेरिका की कैरी गैरिसन ने 50 में से 40 निशाने साधकर स्वर्ण पदक जीता।
- इटली की सोफिया गोरी ने 50 लक्ष्यों के पूरे कोटे में से 39 निशाने साधकर रजत पदक जीता।

खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI) पहल का दूसरा चरण

- खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI) पहलके दूसरे चरण का उद्घाटन 19 जुलाई 2024 को किया गया।
- कीर्ति का लक्ष्य एक एकीकृत प्रतिभा पहचान हेतु ऐसी व्यवस्था बनाना है जो दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं और आधुनिक आईसीटी उपकरणों पर आधारित हो।
- इस पहल से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान को सुव्यवस्थित किया जाएगा और एक ही मंच पर लाया जाएगा।
- इसका लक्ष्य 2024-2025 में 20 लाख मूल्यांकन करना है।
- इससे पहले, 12 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में कीर्ति का पहला चरण शुरू किया गया था।
- 11 खेलों में महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों का मूल्यांकन किया गया।ये खेल तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन और कुश्ती थे।

शौर्य बावा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता

- शौर्य बावा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए।
- शौर्य बावा सेमीफाइनल मेंमिस्र के मोहम्मद ज़कारिया से सीधे गेमों (11-5, 11-5, 11-9) में 41 मिनट में हार गए।

युकी भांबरी ने स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता।

- युकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीता।
- उन्होंने फाइनल में फ्रांस के फैब्रिस मार्टिन और उगो हम्बर्ट को 3-6, 6-3 और 10-6 से हराया।
- युकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी का यह इस साल का दूसरा एटीपी टूर खिताब है।
- इससे पहले जर्मन जोड़ी एंड्रियास मिएस और जान-लेनार्ड स्ट्रूफ को हराकर बवेरियन इंटरनेशनल युगल खिताब जीता था।
- भांबरी ने 2023 में स्पेन में मैलोर्का चैंपियनशिप में लॉयड हैरिस के साथ एटीपी टूर पर अपना पहला खिताब जीता।
- यह स्विस ओपन का 56वां संस्करण था जिसे स्विट्जरलैंड के गस्टाड में रॉय इमर्सन एरिना में आयोजित किया गया था।

लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल

- लिएंडर पेस और विजय अमृतराज 21 जुलाई को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए।
- ये दोनों खिलाड़ी टेनिस खेल से हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई बने हैं।
- लिएंडर पेस 1996 अटलांटा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल कांस्य, आठ पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम खिताब के अलावा डेविस कप में भी जीत चुके है।
- पेस युगल में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रह चुके है तथा 54 युगल खिताब जीते है।
- विजय अमृतराज विंबलडन और यूएस ओपन में दो-दो बार पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और भारत को दो बार 1974 और 1987 में डेविस कप फाइनल में भी पहुंचाया।
- इन्हें रिचर्ड इवांस के साथ 'योगदानकर्ता श्रेणी' में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- इन तीनों के शामिल होने के साथ, हॉल ऑफ फेम में अब 28 देशों के 267 दिग्गज शामिल हो गए हैं।

रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की

- रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर होने के बाद, भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की।
- रोहन बोपन्ना एटीपी टूर इवेंट्स में भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे।
- रोहनबोपन्ना 2024 में टेनिस के ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने थे।
- वर्ष 2017 में उन्होंने फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल खिताब जीता।

जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया

- इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
- उन्होने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002-03 श्रृंखला में खेला था
- जेम्स एंडेसरॉन भारत के सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं।
- एंडरसन ने अपने 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लिए।
- वह श्रीलंका के मुरलीधरन (800 विकेट) और ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न (708विकेट) के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

7. पुरस्कार एवं सम्मान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार

- रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार "द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" से सम्मानित किया।
- यह पुरस्कार भारत-रूस संबंधों को बढ़ावा देने में प्रधान मंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी।
- "द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल" पुरस्कार की स्थापना 300 साल पहले की गई थी।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं।

अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान

- अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन (Olympic movement) में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर (Olympic Order) से सम्मानित किया गया है।
- अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड मैडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं।
- बिंद्रा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं।

ओलंपिक ऑर्डर

- ओलंपिक ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
- 1975 में स्थापित, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने ओलंपिक आंदोलन में विशिष्ट सेवा प्रदान की है।
- अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।

रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

- रोशनी नादर मल्होत्रा को "शेवेलियर डे ला लीजन डी'होनूर" (नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से, भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री थिएरी मथौ ने दिल्ली में रोशनी नादर मल्होत्रा को यह पुरस्कार प्रदान किया।
- रोशनी नादर मल्होत्रा HCL Tech की अध्यक्ष हैं जो कि एक आईटी सेवा कंपनी है।
- यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फ्रांस के लिए असाधारण सेवा की है।

COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024

- भारतीय खगोल भौतिकीविद् प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
- प्रहलाद चंद्र एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष टेलेस्कोप और चंद्रयान 1 चंद्र मिशन सहित प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं।
- श्री अग्रवाल को यह पुरस्कार 15 जुलाई, 2024 को दक्षिण कोरिया के बुसान में दिया गया।
- इसमें पुरस्कार विजेता को पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ एक छोटे ग्रह का नाम देकर सम्मानित किया जाता है। इसलिए "20064 प्रहलाद अग्रवाल" एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है।
- श्री अग्रवाल भारत के प्रथम मल्टी-वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट के प्रमुख अन्वेषक थे, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 28 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया था।

अनिल भारद्वाज विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित

- अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया, जो विकासशील देशों में उत्कृष्ट अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान का सम्मान करता है।
- इस पदक की स्थापना COSPAR और इसरो ने संयुक्त रूप से की है।
- भारद्वाज अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक हैं।
- इस पुरस्कार में पदक और प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ वैज्ञानिक के नाम पर एक लघु ग्रह का नामकरण भी किया जाता है।

मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2024

- आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) ने मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2024 जीता है।
- APCNF 7 साल पहले रायथु साधिकारा संस्था (RySS) के माध्यम से शुरू की गई राज्य सरकार की एक पहल है।
- यह पुर्तगाल स्थित कैलौस्ट गुलबेंकियन फाउंडेशन (CGF) द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है।
- यह पुरस्कार वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- APCNF ने इस वर्ष की एक मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दो अन्य लोगों-प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र स्थित SEKEM के साथ साझा की है।

गांधी मंडेला पुरस्कार 2020

- नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू तुम को 18 जुलाई, 2024 को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया।
- वर्ष 2019 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार परम पावन दलाई लामा को दिया गया।
- ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता रिगोबर्टा मेंचू तुम, ने अपना जीवन स्थानीय अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया।
- रिगोबर्टा मेंचू तुम को 1998 में प्रिंसेस ऑफ़ ऑस्टुरियस पुरस्कार और 1992 में नोबेल शांति पुरस्कारसे सम्मानित किया गया था।
- गांधी मंडेला फाउंडेशन ने मंडेला और गांधी दोनों के मूल्यों को बनाए रखने वाले लोगों को मान्यता देने के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की।

नागालैंड बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित

- नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया।
- बागवानी के विकास के लिए नवीन नीतियों और रणनीतियों को लागू करने में नागालैंड के असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- नागालैंड ने तीन बागवानी फसलों के लिए सफलतापूर्वक जी.आई. पंजीकरण प्राप्त किया है।ये फसलें नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा हैं।
- कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2008 में शुरू किए गए।
- ये पुरस्कार भारतीय कृषि की उन्नति और ग्रामीण समृद्धि लाने के लिए लोगों और समूहों द्वारा किए गए नेतृत्व और असाधारण योगदान का सम्मान करते हैं।

महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार-2024

- महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार-2024 के लिए चुना गया है।
- इसकी घोषणा 5 जुलाई को 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम है।
- महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया
- महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के सहयोग से नंदुरबार जिले में 1.20 लाख एकड़ में फैली हरित पट्टी स्थापित करने की योजना की घोषणा हाल ही में की थी।
- महाराष्ट्र सरकार ने 123 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से लगभग 17 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है।
- महाराष्ट्र, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। राज्य का देश की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 12.92% है।

के. चोकलिंगम को "हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार"

- विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर के. चोकलिंगम को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा हंस वॉन हेंटिग पुरस्कार के लिए चुना गया।
- यह सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे विक्टिमोलॉजी के प्रसिद्ध अग्रदूत हंस वॉन हेंटिग की याद में दिया जाता है।
- यह पुरस्कार हर 3 साल में एक बार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
- डॉ. चोकलिंगम को अपराध विज्ञान और विक्टिमोलॉजी में अपने अध्ययन के लिए कई पुरस्कार मिले हैं।
- डॉ. चोकलिंगम वर्तमान में बेंगलुरु में आर.वी. विश्वविद्यालय में विक्टिमोलॉजी में प्रोफेसर एमेरिटस हैं।

8. चर्चित व्यक्तित्व

9 राज्यों में नए राज्यपाल और पुडुचेरी में नए एलजी की नियुक्ति

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जुलाई 2024 को 9 राज्यों में नए राज्यपाल और पुडुचेरी के नए एलजी को नियुक्ति किया।

नवनियुक्त राज्यपाल और राज्य

1. जिष्णु देव वर्मा – तेलंगाना
2. ओम प्रकाश माथुर – सिक्किम
3. संतोष कुमार गंगवार – झारखंड
4. रामेन डेका – छत्तीसगढ़
5. सी एच विजयशंकर – मेघालय
6. हरिभाऊ किसनराव बागड़े – राजस्थान
7. सी.पी. राधाकृष्णन – महाराष्ट्र (वह पहले तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार के साथ झारखंड के राज्यपाल थे)
8. गुलाब चंद कटारिया – पंजाब के राज्यपाल और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गया है (वह पहले असम के राज्यपाल थे)
9. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य – असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार (वह पहले सिक्किम के राज्यपाल थे)
10. के. कैलाशनाथन – पुडुचेरी के उपराज्यपाल

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है।
- राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

हेमंत सोरेन

- झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
- इससे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया।
- हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले के धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

प्रीति सूदन

- प्रीति सूदन 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की अध्यक्ष बनी।
- प्रीति UPSC की सदस्य तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रह चुकी हैं।
- उनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा, जब वह 65 वर्ष की हो जाएँगी।
- वह आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की (सेवानिवृत्त) आईएएस अधिकारी हैं।
- इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया।

संघ लोक सेवा आयोग

- यह एक संवैधानिक निकाय है।
- इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323तक है।
- इसमें1 अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
- इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनकाकार्यकाल 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक होता है।

एन.कोटिश्वर सिंहऔर आर. महादेवन

- न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिंह (जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) और आर. महादेवन (मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) ने 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई।
- दो न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ वर्तमान मे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है।
- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय कॉलेजियमकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

डॉ. सौम्या स्वामीनाथन

- डॉ. सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया
- प्रो. स्वामीनाथन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाह प्रदान करेंगी, आवश्यक पाठ्यक्रम सुधारों का सुझाव देंगे और अनुसंधान रणनीति पर सलाह देंगी।
- वह विश्व स्तर पर शीर्ष प्रतिभाओं वाले विशेषज्ञ समूह बनाने में भी सहायता करेंगी।
- प्रो. स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी हैं।
- वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक भी रह चुकी है।

गौतम गंभीर

- गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
- उन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया।
- वह इस पद पर 3 वर्ष तक रहेंगे।

- इससे पूर्व गौतम गंभीर 2019 से 2024 तक 17वीं लोकसभा के सदस्य थे।
- उन्हें 2008 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2019 में पद्म श्री मिला।

विनय मोहन क्वात्रा

- विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
- वह 1988 बैच के अधिकारी हैं, इन्हें अप्रैल 2022 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है।

नीता अंबानी

- नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का सदस्य फिर से चुना गया
- उन्हें पेरिस में चल रहे 142वें IOC सत्र में सर्वसम्मति से पुनः चुना गया।
- नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में IOC में शामिल किया गया था।
- नीता अंबानी IOC में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला है।
- वह रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं।
- रिलायंस फाउंडेशन भारत में, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देता है।

जिया राय

- जिया राय (16वर्ष) इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरास्विमर बनी है।
- जिया ने17 घंटे और 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय की।
- यह पैरास्विमर के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती हैं।
- जिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है।
- इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। यह दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है।

के.पी. शर्मा ओली

- के.पी. शर्मा ओली ने 15 जुलाई, 2024 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली।
- नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (CPN-UML) और नेपाली कांग्रेस (NC) के बीच गठबंधन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- नेपाल में 2027 में होने वाले अगले आम चुनावों तक, के.पी.शर्मा ओली और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा बारी-बारी से 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे।
- उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लिया।

कीर स्टार्मर

- कीर स्टार्मर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
- बकिंघम पैलेस में यूनाइटेड किंगडम के सम्राट किंग चार्ल्स III ने 5 जुलाई 2024 को उन्हें यूनाइटेड किंगडम का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया।
- स्टार्मर यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधान मंत्री हैं।
- यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव में कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी ने भारी जीत हासिल की।
- कीर स्टार्मर ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक का स्थान लिया
- यूनाइटेड किंगडम संसद में दो सदन होते हैं:
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ऊपरी सदन)
- हाउस ऑफ कॉमन्स (निचला सदन)
- हाउस ऑफ कॉमन्स 650 सीटों वाला लोकप्रिय निर्वाचित सदन है।
- इस चुनाव में लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत हासिल की जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 119 सीटें मिलीं।

यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम एक संप्रभु देश है जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड शामिल हैं।
- यूनाइटेड किंगडम 1801 में अस्तित्व में आया जब उत्तरी आयरलैंड ग्रेट यूनाइटेड किंगडम के साम्राज्य में शामिल हो गया।
- यूनाइटेड किंगडम का सम्राट राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

मसूद पेज़ेश्कियान

- सुधारवादी नेता मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति चुने गए।
- उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया।
- ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 28 जून 2024 को हुआ था जिसमें चार उम्मीदवार थे।
- इस चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत वोट नहीं हासिल हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान को लगभग 42.5 प्रतिशत वोट और जलीली को 38.7 प्रतिशत वोट मिले।
- राष्ट्रपति चुनने के लिए 5 जुलाई 2024 को आवश्यक रन-ऑफ राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया था। इस बार

पेज़ेश्कियान को 53.7 प्रतिशत वोट और जलीली को 44.3 प्रतिशत वोट मिले।

- 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के हो गई।
- मसूद पेज़ेश्कियान पेशे से हार्ट सर्जन रहे हैं। उन्हें एक हिजाब विरोधी और उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है।

एंटोनियो कोस्टा

- पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है।
- वे वर्तमान अध्यक्ष बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे।

यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद

- यूरोपीय परिषद 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है।
- यह यूरोपीय संघ का राजनीतिक एजेंडा तय करता है।
- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा किया जाता है।
- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो बार चुना जा सकता है।
- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के भीतर सामंजस्य और आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं।
- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यूरोपीय संघ (European Union)

- यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है
- यह मास्ट्रिच संधि के द्वारा अस्तित्व में आया था।
- मास्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ था।

कमला हैरिस

- कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की।
- कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट्रपति हैं।
- कमला वर्तमान में कैलिफ़ोर्निया से सीनेटर तथा भारतीय-अफ्रीकी मूल की नेता हैं।
- पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चार साल की अवधि के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

पॉल कागमे

- पॉल कागमे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
- रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे को 99.15% वोट मिले।
- डेमोक्रेटिक ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार फ्रैंक हबीनेज़ा को सिर्फ़ 0.53% वोट मिले।
- कागमे ने 2003, 2010 और 2017 में 93% से ज़्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की।

रोबर्टा मेट्सोला

- रोबर्टा मेट्सोला को 16 जुलाई को पुनः यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गयाहै।
- मेट्सोला एक माल्टीज़ विधायक हैं जो 2022 में यूरोपीय संघ असेंबली का नेतृत्व करने वाली 20 वर्षों में पहली महिला बनीं थी।
- 1979 में यूरोपीय संघ संसद के सीधे निर्वाचित संस्थान बनने के बाद से वह जर्मनी के मार्टिन शुल्ज़ के बाद एक और कार्यकाल पाने वाली केवल दूसरी अध्यक्ष हैं।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन

- जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयेन दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनेंगी।
- यूरोपीय संसद में 720 सीटों वाले चैंबर में उर्सुला वॉन को 401 वोट मिले।
- उन्होंने यूरोपीय ग्रीन डील को जारी रखने का संकल्प लिया, जो उनके पहले कार्यकाल की एक प्रमुख नीति थी।
- यूरोपीय ग्रीन डील का लक्ष्य 2050 तक, यूरोप को पहला जलवायु-तटस्थ महाद्वीप बनाना है।

क्रिस्टन मिशल

- हाल ही में क्रिस्टन मिशल को एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली।
- क्रिस्टेन मिशल ने काजा कैलास का स्थान लिया।
- मिशल, कैलास की तरह ही उदारवादी रिफॉर्म पार्टी से हैं।
- एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है। तेलिन इसकी राजधानी है।

निकोलस मादुरो

- निकोलस मादुरो को 28 जुलाई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया।
- वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 51% मतों के साथ तीसरी बार जीत हासिल की।
- विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज को 44% मत मिले।
- वेनेज़ुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है।
- इसकी राजधानी कराकास है। वेनेजुएला की मुद्रा वेनेजुएला बोलिवर है।

कमला पुजारी

- प्रसिद्ध कृषिविद् पद्म श्री कमला पुजारी का 74 वर्ष की आयु में कटक में निधन हो गया।
- कमला पुजारी का जन्म ओडिशा के कोरापुट जिले के पात्रापुट गांव में हुआ था।
- कृषि के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019

मेंकमला पुजारी को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था।

- जैविक खेती और देशी चावल की किस्मों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए उन्हें दुनिया भर में सराहना मिली।

इस्माइल हनीयेह

- ईरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हनीयेह की हत्या कर दी गई।
- ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में हनीयेह शामिल हुए थे।
- विदेश मामलों में हनीयेह ने फिलिस्तीनी संगठन के चेहरे के रूप में काम किया।
- 2017 में, हनीयेह को खालिद मेशाल की जगह हमास राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना गया था।
- इज़राइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था जिसमें 1,195 लोगों की जान चली गई थी, इसकी जिम्मेदारी हमास ने ली थी।

गुयेन फु ट्रोंग

- हाल ही में वियतनाम के सबसे शक्तिशाली नेता और पूर्व राष्ट्रपति गुयेन फु ट्रोंग का निधन हो गया।
- वह 2018 से 2020 तक वियतनाम के राष्ट्रपति रहे तथा विदेश नीति के स्तर पर उन्हें **'बैम्बू डिप्लोमेसी' (bamboo diplomacy)**के लिए जाना जाता है।
- इस कूटनीति के तहत उन्होंने चीन और अमेरिका दोनों के साथ बेहतर संबंध रखे।
- इस तरह उन्होंने बांस की तरह लचीले रहते हुए "अधिक मित्र, कम शत्रु" रखने की वकालत की।
- इसके तहत बढ़ती जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा के बीच प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए देश की अप्रोच को बांस यान बैम्बू के समान बताया गया जो बिना टूटे हवा में झुक जाता है।

9. चर्चित स्थल

असम का मोइदाम भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल बना

- असम के मोइदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है।
- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है।
- नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति की बैठक में मोइदाम को शामिल करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
- मोइदाम ईंट, पत्थर के लगभग 700 साल पुराने खोखले तहखाना हैं।
- इनमें ताई-अहोम के राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अवशेष हैं।
- मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पूर्वोत्तर का तीसरा धरोहर स्थल और पहला सांस्कृतिक स्थल है।
- दो अन्य काजीरंगा और मानस हैं जिन्हें प्राकृतिक विरासत श्रेणी के अंतर्गत अंकित किया गया था।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे अधिक 59 स्थल इटली के हैं, इसके बाद 57 स्थलों के साथ चीन का स्थान है। भारत 43 स्थलों के साथ छठे स्थान पर है।
- 1983 में अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा स्थित ताज महल और आगरा का किला, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल थे।

यूनेस्को में शामिल भारत के धरोहर स्थल

- यूनेस्को ने भारत में 43 स्थानों, शहर, इमारतों, गुफाओं आदि को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर शामिल हैं। यूनेस्को में शामिल भारत के धरोहर स्थल इस प्रकार हैं:

क्र.	विश्व विरासत स्थल	वर्ष	संबंधित राज्य
1.	आगरा का किला	1983	उत्तर प्रदेश
2.	अजंता की गुफाएं	1983	महाराष्ट्र
3.	एलोरा की गुफाएं	1983	महाराष्ट्र
4.	ताज महल	1983	उत्तर प्रदेश
5.	महाबलीपुरम के स्मारक	1984	तमिलनाडु
6.	सूर्य मंदिर	1984	ओड़िशा
7.	मानस वन्यजीव अभ्यारण्य	1985	असम
8.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1985	असम
9.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	1985	राजस्थान
10.	गोवा के चर्च	1986	गोवा
11.	फतेहपुर सीकरी	1986	उत्तर प्रदेश
12.	हम्पी के स्मारक	1986	कर्नाटक
13.	खजुराहो के मंदिर	1986	मध्य प्रदेश
14.	एलीफेंटा की गुफाएं	1987	महाराष्ट्र
15.	महान चोल मंदिर	1987/ 2004	तमिलनाडु
16.	पट्टाकल के स्मारक	1987	कर्नाटक
17.	सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान	1987	पश्चिम बंगाल
18.	नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी	1988/ 2005	उत्तराखंड
19.	सांची का स्तूप	1989	मध्य प्रदेश
20.	हुमायूं का मक़बरा	1993	दिल्ली
21.	क़ुतुब मीनार	1993	दिल्ली
22.	भारत के पर्वतीय रेलवे (दार्जिलिंग/नीलगिरी/शिमला)	1999/ 2005/ 2008	पश्चिम बंगाल/ तमिलनाडु/ हिमाचल प्रदेश
23.	महाबोधि मंदिर	2002	बिहार
24.	भीमबेटका गुफ़ाएं	2003	मध्य प्रदेश
25.	चंपानेर – पावागढ़ पार्क	2004	गुजरात
26.	छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस	2004	महाराष्ट्र
27.	लाल किला	2007	दिल्ली
28.	जंतर-मंतर	2010	राजस्थान
29.	पश्चिमी घाट	2012	गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
30.	राजस्थान के पहाड़ी किले	2013	राजस्थान
31.	रानी की वाव	2014	गुजरात
32.	ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	2014	हिमाचल प्रदेश
33.	नालंदा	2016	बिहार

34.	कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान	2016	सिक्किम
35.	ली कार्बुसियर के स्थापत्य कार्य	2016	चंडीगढ़
36.	अहमदाबाद शहर	2017	गुजरात
37.	विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको	2018	महाराष्ट्र
38.	जयपुर	2019	राजस्थान
39.	काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर	2021	तेलंगाना
40.	धोलावीरा	2021	गुजरात
41.	शान्तिनिकेतन	2023	पश्चिम बंगाल
42.	होयसल मंदिर समूह	2023	कर्नाटक
43.	मोइदाम	2024	असम

भारतीय संविधान में प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार 'यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि यह अपनी समृद्ध मिश्रित सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और संरक्षण करें'।

यूनेस्को (UNESCO)

- UNESCO:संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)
- यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है।
- गठन:4 नवंबर 1946 को।
- मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस)
- वर्तमान अध्यक्ष: आंद्रे अजोले।

महाबोधि मंदिर (बोधगया):'विशाल वास्तुशिल्प संपदा'की मौजूदगी के प्रमाण मिले

- हाल ही में बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसरऔर उसके आसपास के क्षेत्र में "विशाल वास्तुशिल्प संपदा" की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं।
- यह अध्ययन कला, संस्कृति और युवा विभाग की एक शाखा बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी (BHDS) द्वारा यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया।
- महाबोधि मंदिर फल्गु नदी के पश्चिम में है, और सुजाता स्तूप और कई अन्य पुरातात्विक अवशेष नदी के पूर्व में स्थित हैं।
- नदी के पूर्व में स्थित स्मारक और अन्य पुरातात्विक अवशेष महाबोधि मंदिर से स्वतंत्र माने जाते हैं।
- नवीनतम खोज के अनुसार मंदिर और सुजाता स्तूप दोनों ही अन्य पुरातात्विक अवशेषों के साथ अतीत में एक ही नदी के तट पर थे।

महाबोधि मंदिर परिसर

- महाबोधि मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- यह भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है।
- बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
- यहाँ पहला मंदिर सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है।
- यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है।

गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें: दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोल माइंस में शामिल

- छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है।
- ये दोनों खदानें छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थितहै।
- ये खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है।

फरीदाबाद: स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित एशिया की पहली 'प्री-क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा'

- हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट" (THSTI), फरीदाबाद में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन (CEPI) के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित "प्री-क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा" शुरू की गई है।
- यह सुविधा विश्व की 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और एशिया में पहली ऐसी प्रयोगशाला है।
- महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन (CEPI) ने BSL3 रोगजनकों को संभालने की क्षमता के आधार पर BRIC-THSTI को प्री-क्लिनिकल नेटवर्क प्रयोगशाला विकसित की गई है।
- इसके अलावा जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन (Ge-HuMic) सुविधा का भी उद्घाटन किया।
- यह अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को माइक्रोबियल कल्चर उपलब्ध कराने हेतु एक भण्डार के रूप में कार्य करेगा।

राजकोट: अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र (iCAL)

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 18 जुलाई को राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र (iCAL) का उद्घाटन किया।
- iCAL देश में अपनी तरह का पहला संस्थान है।

- उद्देश्य: स्थानीय शासन निकायों के लेखा परीक्षण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है।
- iCAL स्थानीय सरकारों से जुड़े नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखा परीक्षकों के लिए एक सहयोगी मंच होगा।
- यह स्थानीय सरकार के लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता को बढ़ाएगा ताकि बेहतर वित्तीय प्रदर्शन मूल्यांकन, सेवा वितरण और डेटा रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।
- यह स्थानीय सरकार के लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में भी काम करेगा।

चेन्नई: 6G के लिए क्लासिकल और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र

- हाल ही में चेन्नई के IITM रिसर्च पार्क में "6G के लिए क्लासिकल और क्वांटम संचार" पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- यह दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (TCoE)-भारत का एक उप-केंद्र है और 6G तकनीक के विकास और तैनाती का नेतृत्व करेगा।
- यह केंद्र अत्याधुनिक परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा।
- यह केंद्र IIT मद्रास में स्थित 5G टेस्ट बेड के बीच इंटरकनेक्शन की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- नोट: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मार्च, 2023 को भारत के 6G विजन से संबंधित "भारत 6G विजन" डॉक्यूमेंट जारी किया था।

JN बंदरगाह (मुंबई) : भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा

- भारत की पहली एकीकृत कृषि-निर्यात सुविधा (Integrated Agri-Export Facility) मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'पीपीपी मोड पर निर्यात-आयात सह घरेलू कृषि वस्तु-आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का विकास' परियोजना को मंजूरी दी है।
- यह सुविधा लॉजिस्टिक्स में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाएगी।
- यहसुविधा गैर-बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात मे सहायक सिद्ध होगी।
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंडलॉर्ड बंदरगाह है जिसमें सभी बर्थ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित किए जा रहे हैं।

हुमायूं का मकबरा (दिल्ली): भारत का पहला संकेन म्यूजियम

- हाल ही में दिल्ली में हुमायूं के मकबरे कॉम्प्लेक्स में भारत के पहले संकेन म्यूजियम (sunken museum) का उद्घाटन कियागया।
- संग्रहालय में मुगल लघु चित्र, पांडुलिपियाँ, महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प तत्व, सिक्के, समकालीन कला, एस्ट्रोलैब, पत्थर के शिलालेख, कांच के बने पदार्थ और वस्त्र शामिल हैं।
- इसका लेआउट मध्ययुगीन 'बाओली' या पारंपरिक पानी की टंकियों से प्रेरित है, मुगल सम्राट हुमायूँ की विरासत को दर्शाता है।
- यह संग्रहालय आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा ASI की साझेदारी में विकसित किया गया है।
- नोट: हुमायूं का मकबरा परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

सैन फ्रांसिस्को:विश्व की पहली हाइड्रोजन-संचालित वाणिज्यिक नौका लॉन्च

- 100% हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका, एमवी सी चेंज (MV Sea Change), 19 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च की गई।
- यह नौका75 यात्रियों को ले जाने मे सक्षम है।
- प्रदूषक उत्सर्जित करने वाली वर्तमान डीजल-संचालित नौकाओं के विपरीत, हाइड्रोजन-संचालित सी चेंज केवल गर्मी और जल वाष्प को उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न करती है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह सेवा छह महीने तक निःशुल्क रहेगी।
- सी चेंज लगभग 300 समुद्री मील की यात्रा कर सकता है और ईंधन भरने की आवश्यकता होने से पहले 16 घंटे तक काम कर सकता है।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर बिजली का उत्पादन करते हैं।
- इस परियोजना का वित्तपोषण और प्रबंधन स्विच मैरीटाइम द्वारा किया गया।

गुरुग्राम:राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन

- REC लिमिटेड के 55वें स्थापना दिवस पर आरईसी मुख्यालय, गुरुग्राम में 25 जुलाई को राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम (NFMS) नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया।
- यह REC लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, RECPDCLद्वारा विकसित किया गया है
- उद्देश्य: 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की निगरानी करना है।
- NFMS देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति, बिजली कटौती और विस्तृत जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है।
- यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्यान्वयन योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।
- इससे वितरण उपयोगिताओं (डिस्कॉम) में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी और अंततः अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

शिंकुन ला सुरंग:विश्व की सबसे ऊंची सुरंग

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर 26 जुलाई को शिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया।
- यह लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर निमू-पदुम-दारचा सड़कलिंक पर स्थित है।
- इसके तहत 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जाएगा।
- इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया जाएगा।
- यह हिमाचल प्रदेश और केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगी
- यह सुरंग पश्चिमी लद्दाख और जस्कर घाटी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
- इस सुरंग का निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। वर्तमान में चीन की मीला टनल 15590 फीट की ऊंचाई पर है।
- यह सुरंग चीन की सीमा पर चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध होगी।
- इससे सीमा तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में आसानी होगी।

प्रकाशम (आंध्र प्रदेश):विश्व के सबसे पुराने ज्ञात शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज

- आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में पुरातत्वविदों की एक टीम ने 41,000 साल पुराने शुतुरमुर्ग (ostrich) के घोंसले की खोज कीहै।
- इस घोंसले की चौड़ाई 9-10 फीट है, और कभी इसमें 9-11 अंडे रहते थे।
- यह अभूतपूर्व खोज प्राचीन शुतुरमुर्गों के जीवन और विलुप्त होने पर प्रकाश डालती है।

शुतुरमुर्ग

- शुतुरमुर्ग (स्ट्रूथियो कैमलस) अफ्रीका की नेटिव प्रजाति है और यह पक्षी उड़ नहीं सकता है।
- शुतुरमुर्ग को उसकी लंबी गर्दन के कारण "कैमल बर्ड" के नाम से जाना जाता था।
- शुतुरमुर्ग उच्च तापमान सहन कर सकता है और लंबे समय तक पानी के बिना रह सकता है।
- अफ्रीका के गर्म सवाना और खुले जंगलों में पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है।

10. महत्त्वपूर्ण तथ्य

गणतंत्र मंडप' और "अशोक मंडप"

- राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर 'गणतंत्र मंडप' कर दिया गया है।
- पारंपरिक रूप से इसका उपयोग राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और उत्सवों के लिए किया जाता है।
- राष्ट्रपति भवन में बॉलरूम के रूप में डिजाइन किए गए अशोक हॉल को अब अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा।
- यहभारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ संरेखित करने के लिए नाम परिवर्तन किए गए थे।

46वाँ विश्व धरोहर समिति सत्र

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया।
- विश्व धरोहर समिति की बैठक **भारतमें पहली बार आयोजित** की गई।
- विश्व धरोहर समिति की बैठक प्रतिवर्ष होती है
- यहसमिति विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेती है।

विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES)

- इसका आयोजन गोवा में 20 से 24 नवंबर, 2024 तक किया जाएगा।
- वेव्स भारत के मनोरंजन क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
- वेव्स मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र में चर्चा, व्यापार सहयोग और नवाचार के लिए एक अग्रणी मंच है।

'लड़का भाऊ' नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना

- यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के लिए शुरू की गई है।
- यह योजना महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर शुरू की गई।
- इस योजना के तहत, 12वीं कक्षा उत्तीर्णरोजगार योग्य व्यक्ति को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
- पात्र व्यक्ति को उद्योग में प्रशिक्षण के दौरान सरकार से यह वजीफा मिलेगा।
- इससे पहले, राज्य बजट में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना की घोषणा की गई थी।
- इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया।
- इसमें पात्रता हेतु लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक सीमित होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य' बना

- मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य' श्रेणी में पहले स्थान पर रहा।
- यह योजना 2020 में स्ट्रीट वेंडोर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट योजना शुरू कीगई
- इसमें 50,000 रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिए जाने का प्रावधान है।
- 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्थानीय शहरी निकाय (ULB) - मेगा और मिलियन प्लस शहरों के साथ ऋण' श्रेणी में, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पहला स्थान हासिल किया।
- इसके अलावा **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) पुरस्कारों** की घोषणा की गई, जिसमें केरल 'सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग (SPARK)' श्रेणी में पहले स्थान पर है।
- इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

MeDevIS प्लेटफॉर्म

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने MeDevIS (मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- यह मेडिकल डिवाइसेज की जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है।
- इसे सरकारों, रेगुलेटरी बॉडी और यूजर्स को रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के डायग्नोस्टिक, टेस्ट और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग पर निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- MeDevIS प्लेटफ़ॉर्म में 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस शामिल हैं जिनका उपयोग व्यापक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए किया जाता है।
- इसमें प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और साथ ही संक्रामक रोग जैसे COVID-19 शामिल हैं।

संज्ञान ऐप

- रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-संज्ञान ऐप (Sangyaan App) लॉन्च किया गया है
- इसे RPF की तकनीकी टीम द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों: भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य RPF कर्मियों को नए और पुराने दोनों आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को समझने के लिए व्यापक जानकारी प्रदान करके शिक्षित और सशक्त बनाना है।

मानस (MANAS) हेल्पलाइन

- मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मानस (MANAS) हेल्पलाइन लॉन्च की गई है।
- यह राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जिसका पूरा नाम मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्रहै।
- मानस में एक टोल-फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और उमंग ऐप शामिल है।
- इससे नागरिक नशीली दवाओं की तस्करी पर जानकारी साझा करने या नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशामुक्ति और पुनर्वास जैसी समस्याओं से संबंधित परामर्श के लिए गुप्त रूप जुड़ सकेंगे।

राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC) और भूसंकेत वेब पोर्टल

- केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 19 जुलाई को कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC) का उद्घाटन किया।
- इसके अलावा भूसंकेत वेब पोर्टल (Bhusanket Web Portal) और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।

राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (NLFC)

- NLFC भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है।
- इससे कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और नीलगिरि जिलों के निवासियों को 20 जुलाई 2024 से साझा की जाने वाली लाइव पूर्वानुमान रिपोर्ट का लाभ मिलना हुआ।
- यह नियत समय में भूस्खलन से प्रभावित सभी राज्यों के लिए अर्ली वार्निंग बुलेटिन जारी करेगा।
- यह 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम (LEWS) का संचालन करेगा।

भूसंकेत वेब पोर्टल

- यह वेब पोर्टल भूस्खलन (landslide) के खतरों पर प्रासंगिक डेटा और सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे देश में शॉर्ट रेंज और मेडियम रेंज के भूस्खलन पूर्वानुमान (landslide forecasting) की शुरुआत होगी।

पर्यावरण

COP292024

- इसका आयोजन 11-22 नवंबर 2024 को बाकू (अजरबैजान) में किया जाएगा।
- जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए COP29 प्रेसीडेंसी की योजना का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा।

"क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड"

- COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के मेजबान अज़रबैजान ने "क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड" शुरू किया।
- "क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड" (CFAF) जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक योगदान प्राप्त करेगा।
- यह फंड विकासशील देशों के साथ-साथ अन्य देशों को 1.5C तापमान लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा।
- प्रारंभ में, 1 बिलियन डॉलर सदस्यों के माध्यम से निश्चित राशि के रूप में या उत्पादन मात्रा के आधार पर वार्षिक योगदान के साथ जुटाए जाएंगे।

Ideas4LiFE पोर्टल

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 जुलाई को उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए Ideas4LiFE शुरू किया गया।
- यह पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करेगा।
- **उद्देश्य:** छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ की वैश्विक पहलों में अपने नवीन विचारों का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है।
- यह पोर्टल प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचार ऑनलाइन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

11. इंडेक्स एवं रिपोर्ट्स

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24

- सतत विकास लक्ष्यों (SDG) का चौथा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया।
- यह इंडेक्स पर राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय (राज्य) स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापता है।
- SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क से जुड़े 113 संकेतकों पर राष्ट्रीय प्रगति को मापता है।
- इसके तहत वर्ष 2023-24 के लिए भारत काSDG स्कोर 71 है(2020-21 में 66 था)।
- **देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में हैं।**
- यह इंडेक्स, जो 1 से 100 के स्केल पर 16 लक्ष्यों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है
- इसमें केरल और उत्तराखंड को 79-79 अंकों के स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बने है
- बिहार 57 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर है।
- 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश (स्कोर में 25 की वृद्धि) हैं।
- गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में हुई प्रगति के कारण इसमें सुधार हुआ है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में, शीर्ष पांच प्रदर्शन करने वाले चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली है।

हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट-2024

- यह रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की जाती है।
- यह रैंकिंग देशों के पासपोर्ट की ताकत पर निर्भर करती है।
- इसमें देश के पासपोर्ट के जरिए बगैर वीजा या वीजा ऑन अराइवल सबसे अधिक देशों में आने-जाने की छूट होती है, उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है।
- इस रिपोर्ट में भारत 82वें स्थान पर है।
- भारत की रैंकिंग में पिछले रैंकिंग रिपोर्ट से 2 स्थान का सुधार हुआ है।
- सिंगापुर, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया।
- भारतीय पासपोर्ट धारक भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मकाऊ, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, सेशेल्स, जिम्बॉब्वे, यूगांडा, ईरान और कतर सहित 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं।
- सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 195 देशों की वीज़ा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन हैं।
- 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे निचले, 103वें स्थान पर है।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024

- यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी किया गया है।
- यह इंडेक्स सततता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित पाँच प्रमुख श्रेणियों में 173 शहरों की रहने योग्य आधार पर रैंक करता है।
- इसमें ऑस्ट्रिया का वियना शहर रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है।
- इसके बाद स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर का स्थान है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के चार शहर- ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी, जापान में ओसाका और न्यूजीलैंड में ऑकलैंड- इस साल दुनिया के शीर्ष दस सबसे रहने योग्य शहरों में शामिल हुए हैं।
- 173वें स्थान पर, कराकास (वेनेजुएला) दुनिया का सबसे बदतर शहर है।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी (22 जुलाई को जारी) की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है।
- इस अवधि के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में भारत तीसरा स्थान पर रहा है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार चीन 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है।
- ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है।
- इस रिपोर्ट में वनों की कटाई में उल्लेखनीय कमी का भी उल्लेख है।
- इंडोनेशिया में 2021 से 2022 तक वनों की कटाई में 8.4% की गिरावट हुई।

वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) द्वारा जारी की गई।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है और फिर 12% की गिरावट आएगी, लेकिन भारत इस पूरी सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा।
- भारत, वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया था, यह 2100 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा।

वैश्विक डिजिटल भुगतानों में भारत का योगदान लगभग आधा है

- भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक डिजिटल भुगतान का 48.5% भारत में किया जाता है।
- वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10वां हिस्सा बनाती है।
- भारत में डिजिटल भुगतान ने पिछले 7 वर्षों में मात्रा के संदर्भ में 50% और मूल्य के संदर्भ में 10% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 115.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके वैश्विक प्रेषण में पहले स्थान पर रहा।
- इसके अनुसार हमलों की घटनाएँ 2017 में 53,117 से बढ़कर जनवरी-अक्टूबर 2023 के दौरान 13,20,106 हो गई हैं।

12. महत्त्वपूर्ण दिवस

विश्व जूनोसिस दिवस 2024

- यह दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है।
- यह दिवस लुई पाश्चर के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 6 जुलाई, 1885 को एक जूनोटिक बीमारी रेबीज का पहला सफल टीका लगाया था।
- जूनोसिस ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती हैं।
- ज़ूनोसिस संक्रामक रोग हैं जो जानवरों और मनुष्यों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं, जैसे रेबीज, एंथ्रेक्स, इन्फ्लूएंजा (H1N1 और H5N1), निपाह, COVID-19, ब्रुसेलोसिस और तपेदिक।
- ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी और कवक सहित विभिन्न रोगजनकों के कारण होते हैं।

102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024

- यह दिवस इस वर्ष 6 जुलाई को मनाया गया।
- इस वर्ष की थीम "सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है" (Cooperatives Building a Better Future for All) थी।
- यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।
- इसे पहली बार 2005 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया गया था
- भारत में केंद्र सरकार ने तीन मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव संस्थाएं बनाई हैं – जैविक यानी आर्गेनिक समिति, निर्यात समिति और बीज समिति।
- PACS सहकारी समितियां हैं और यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य सूची का विषय है।

विश्व जनसंख्या दिवस

- प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (थीम)- 'किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना' (Leave no one behind, count everyone) है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा 1989 में की थी।
- पहली बार 11 जुलाई 1990 को यह दिवस मनाया गया था।

विश्व युवा कौशल दिवस

- प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day) मनाया जाता है।
- यह दिवस युवाओं को अधिक से अधिक कौशल विकास के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम (विषय)- 'शांति और विकास के लिए युवा कौशल' (Youth Skills for Peace and Development) है।
- विश्व युवा कौशल दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गयी थी।
- पहली बार 15 जुलाई 2015 को यह दिवस मनाया गया था।

नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024

- यह प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया
- यह पहली बार 18 जुलाई 2010 को मनाया गया।
- वर्ष 2024 का विषय "गरीबी और असमानता से मुकाबला करना हमारे हाथ में है।" है
- मंडेला दक्षिण अफ्रीका में 'राष्ट्रपिता' के रूप में जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2024

- यह प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है।
- यह दिवस शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है।
- यूनेस्को ने 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना के उपलक्ष्य में 1966 से यह दिवस मनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024

- यह प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है।
- इस दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की शुरुआत की गई थी।
- आयकर विभाग ने कर लगाने के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2010 में पहली बार इस दिन को मनाने का निर्णय लिया।

कारगिल विजय दिवस

- यह दिवस कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को

श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है।

- वर्ष 2024 में कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ है।
- कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई, 1999 के बीच नियंत्रण रेखा (LOC) पर हुआ था।
- इसके तहत भारतीय सेना द्वारा "ऑपरेशन विजय" चलाया गया।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024

- यह प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है।
- यह हेपेटाइटिस वायरल के खिलाफ़ जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का विषय "यह कार्य करने का समय है" है।
- यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक ब्लमबर्ग की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है।
- प्रारंभ में, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 19 मई को मनाया जाता था लेकिन बाद में 2010 में इसे 28 जुलाई को मनाया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

- प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day) मनाया जाता है।
- यह दिवस बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था।
- वर्ष2024 का विषय- 'कार्रवाई का आह्वान' (Call for Action) है।

भारत में बाघों की स्थिति

- भारत सरकार ने देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1973 में प्रॉजेक्ट टाइगर शुरू किया था।
- 1973-74 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्यश थे और अब इनकी संख्याण बढकर 54 हो गई है। दुनिया में बाघों की कुल संख्या के मामले में भारत पहले स्थान पर है।
- पर्यवारण मंत्रालय ने 2005 में नैशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) का गठन किया था। प्रॉजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी NTCA सौंपी गई थी।
- बाघ, भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है।
- बाघ आकलन रिपोर्ट-2023के अनुसार वर्तमान में विश्व में बाघों की कुल संख्या का लगभग 75 प्रतिशत भारत में है।
- बाघों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश (785)में पाई गई है

केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाएगी

- पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में आतंरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी।
- आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के बारे में जागरूक करने हेतु भारत सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह आपातकाल देश में 25 जून 1975 से प्रभावी हुआ और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ था।
- इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जारी किया था।
- 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, इसे आंतरिक अशांति के आधार पर हटाकर "सशस्त्र विद्रोह" कर दिया गया।